



‘जब अलावेरु ने सभी निर्णय लिए बिहार में, तो वो हार की जिम्मेवारी भी लें’

अन्ततोगत्वा कांग्रेस ने हार स्वीकार की बिहार में और शुक्रवार को हार का विश्लेषण करने के लिए उच्चस्तरीय बैठक रखी है दिल्ली में

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवंबर कांग्रेस को आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ा है कि वह बिहार चुनाव हार गई है। गुरूवार 27 जनवरी को पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और बिहार कांग्रेस इकाई बैठक करेंगे और बिहार में मिली जबरदस्त पराजय पर मंथन करेंगे। बिहार में कांग्रेस ने 61 में से केवल 6 सीटें जीती हैं।

नई दिल्ली से पटना तक सभी हथियार अब बाहर आ चुके हैं, क्योंकि यह अपेक्षित है कि वरिष्ठ नेता और नई टीम, जो राहुल गांधी के संरक्षण में आकर पार्टी चला रही है, के बीच करारी भिड़ंत में कोई कसर नहीं रहेगी।

संकट के केन्द्र में कृष्णा अलावेरु हैं, जो एआईसीसी के बिहार प्रभारी थे और जिन्होंने अपनी टीम के साथ सभी

- बैठक में वरिष्ठ नेताओं ने अपने-अपने चाकू-छुरी तैयार कर रखे हैं, राहुल की युवा टीम की सर्जरी के लिए।
- फ्री व फ्रैंक मंथन करने देने का वादा किया गया है। अतः पूरा घमासान होने की संभावना है, बैठक में।
- अलावेरु का रवैया यह तर्क प्रस्तुत कर रहा है कि वे अगली पीढ़ी के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, पर, उनके इस तर्क को कोई स्वीकार करता नहीं दिख रहा है।
- एक अन्य ग्रुप यह तर्क दे रहा है कि पार्टी को आरजेडी (तेजस्वी यादव) के चंगुल से मुक्ति लेकर, अपने ही दम पर चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी ने सभी हथकंडे अपनाये थे, कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने के लिए।
- अगर, बैठक में “फ्री व फ्रैंक” बातचीत का मौका नहीं दिया गया तो कांग्रेस का सूरज डूबता सा लग रहा है।

फैसले लिए, चाहे कोई भी कुछ कहे। वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि

अगर अलावेरु और उनकी टीम ने बिना किसी से सलाह-मशवरे के सारे फैसले

किए, तो उन्हें नतीजों की पूरी जिम्मेदारी (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

‘कर्नाटक में नेतृत्व संकट है, सोनिया, राहुल और मैं इसे फिक्स कर देंगे’

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में नेतृत्व संकट की बात स्वीकार की

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 26 नवंबर कांग्रेस अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को कर्नाटक के नेतृत्व-संकट के जगजाहिर घटनाक्रम को स्वीकार किया और जोर देकर कहा कि राज्य में पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार (डीकेएस) के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान का समाधान जल्द हो जाएगा।

पार्टी अध्यक्ष ने आज दोपहर बाद कहा, “सोनिया (गांधी), राहुल (गांधी), और मैं इसे सुलझा लेंगे, सूत्रों ने भी कहा कि 1 दिसंबर, जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, तक इसका समाधान मिल जाएगा।

सूत्रों ने यह भी कहा कि खड़गे और राहुल गांधी की एक बैठक अगले 48

- सूत्रों ने बताया कि अगले 48 घंटों में खड़गे व राहुल की मीटिंग होगी, फिर मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उन्हें चुनौती दे रहे डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया जाएगा।
- अब जाकर कांग्रेस ने औपचारिक रूप से माना है कि पार्टी शासित कर्नाटक में नेतृत्व संकट है। पार्टी की सरकार सिर्फ तीन राज्यों में है। इनमें से एक में सरकार पर संकट मंडरा रहा है।
- यह स्वीकारोक्ति एक सप्ताह पहले पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा किए गए इस दावे के विपरीत है कि पार्टी में सब ठीक है।

घंटों में होने की संभावना है, इसके बाद, संभवतः शुक्रवार को सिद्धारमैया और डीकेएस को दिल्ली बुलाया जाएगा। यह कि कांग्रेस ने अब इस सत्ता

संघर्ष को उस राज्य में, जो उन तीन राज्यों में से एक है, जहाँ उसकी सत्ता है, और जहाँ अगले दो साल में चुनाव होने (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

राहुल गांधी ने 26/11 के शहीदों को श्रद्धांजलि दी

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने ‘26/11’ मुंबई आतंकवादी हमले में अपने प्राण गंवाने वाले नागरिकों और सुरक्षाकर्मियों को बुधवार को श्रद्धांजलि

- उन्होंने कहा कि सुरक्षाकर्मियों व आम नागरिकों के साहस और बलिदान को देश कभी नहीं भूलेगा।

अर्पित की और कहा कि उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा।

गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, मुंबई में 26/11 को हुए दुस्साहसी आतंकवादी हमले में अपने प्राण गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। भारत उनके साहस, बलिदान और शहादत को कभी नहीं भूलेगा।

(श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

विद्याधर नगर में पैंथर ने बछड़े का शिकार किया

जयपुर, 26 नवम्बर। जंगल में खाना –पीना नहीं मिलने के कारण अब जंगली जानवरों का मूवमेंट रिहायशी इलाकों में आए दिन नजर आ रहा है। वीवीआईपी इलाके में लैपड के मूवमेंट के बाद, शास्त्री नगर व विद्याधर नगर इलाके में मंगलवार देर रात दो बजे लैपड के होने की सूचना मिली। तुरंत ही यह सूचना पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई और इलाके में दहशत व्याप्त हो गई।

सेक्टर –10 शिव मंदिर के पुजारी सुधांशु ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब दो बजे कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज आई। काफी देर तक कुत्तों के भौंकने पर बाहर जाकर देखा तो सब

- वन विभाग की टीम के प्रयासों के बाद भी पैंथर अभी पकड़ा नहीं गया।

कुछ ठीक लगा। लेकिन बुधवार सुबह मंदिर-परिसर में स्थित बगीचे में एक बछड़ा मरा हुआ मिला। बगीचे में घास के आसपास लैपड के पद- चिन्ह भी दिखाई दिए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इसके बाद बुधवार दोपहर पानी पेच इलाके में लैपड का मूवमेंट दिखाई दिया।

रिहायशी इलाकों में पहले भी लैपड का कई बार मूवमेंट देखा जा चुका है। सिविल लाइंस, विद्याधर नगर, दुर्गापुरा, गोपालपुरा, जयसिंह पुरा, जगतपुरा, (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

बिहार में स्पीकर की पोस्ट पर भाजपा से सीधी टक्कर ली जद (यू) ने

गृह मंत्रालय पद गंवाने के बाद अपनी ताकत दिखाने के लिए जद (यू) ने यह रणनीति अपनाई है

- भाजपा ने पार्टी के 8 बार के विधायक एवं अनुभवी दलित नेता प्रेम कुमार का नाम स्पीकर के पद के लिए पहले ही दे दिया था। पर, अब जद (यू) ने अचानक से अपने चार बार के विधायक दामोदर रावत का नाम आगे कर दिया है।
- इससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है।
- अब सवाल यह है कि एक दिसंबर से नई विधानसभा का सत्र क्या सत्तारूढ़ गठबंधन, एनडीए की दरारों के साए में होगा।

में विस्वास की बढ़ती कमी का झोतक बन गया है।

रिपोर्टर्स के मुताबिक, तनाव सरकार के गठन के शीघ्र बाद तभी शुरू हो गया था, जब गृह मंत्रालय, जिसे नीतीश कुमार ने लगभग दो दशकों तक संभाला था, भाजपा के पास चला गया था। जदयू के नेताओं ने इस कदम को भाजपा के दबदबे एवं प्रभुत्व की अप्रत्याशित पुष्टि के रूप में देखा, जबकि भाजपा के रणनीतिकारों का कहना है कि

यह पोर्टफोलियो वितरण नई गठबंधन व्यवस्था में “शक्ति समानता” को दर्शाता है।

अब, जब सत्र की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है, दोनों दल विधानसभा में टकराव से बचने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। बताया जाता है कि भाजपा और जदयू के वरिष्ठ नेता एक ऐसा फॉर्मूला तलाश रहे हैं, जिससे दोनों की साख बच जाए। (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

राबड़ी देवी को सरकारी बँगला खाली करने का नोटिस, आखिर क्यों?

अंदरूनी चर्चा है कि नीतीश कुमार ने यह कदम भाजपा के दबाव में उठाया है

- यह संकेत है कि भाजपा बिहार सरकार में अपना दबदबा कायम करना चाहती है।
- राबड़ी देवी का बँगला, 10 सर्कुलर रोड, गत दस साल से लालु परिवार का केन्द्र है। यह विशाल बँगला मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने है।
- सवाल यह है कि नीतीश तो इतने सालों से मुख्यमंत्री हैं, फिर बँगला खाली करने का नोटिस अब क्यों दिया गया, वो भी एकाएक, क्या इसके पीछे भाजपा का दबाव है।
- इस नोटिस का आधार पटना हाई कोर्ट के 19 फरवरी 2019 के फैसले को बताया गया है, जो तेजस्वी की याचिका पर आया था, तब तेजस्वी ने उपमुख्यमंत्री का बँगला खाली करने के नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने तेजस्वी की याचिका खारिज कर आदेश दिया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों से बँगला, स्टफ आदि सुविधाएं वापस ली जाएं।

राबड़ी देवी के पास बँगला खाली करने के अलावा शायद कोई विकल्प नहीं है। हालांकि राजद इस मुद्दे पर सहानुभूति

नहीं करेंगी। राजद की बिहार इकाई के अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने एनडीए पर लालु प्रसाद यादव के प्रति मन में द्वेष रखने का आरोप लगाया और कहा कि मुख्यमंत्री ने यह कदम “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को खुश करने के लिए” उठाया है। उनकी यह सोच पूरी तरह निराधार भी नहीं लगती, क्योंकि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने कभी राबड़ी देवी को सर्कुलर रोड वाला बँगला खाली कराने की पहल नहीं की। ऐसी स्थिति में, यह प्रश्न उठता ही है कि यह कदम एकाएक अब क्यों?

देश के अन्य हिस्सों की तरह सरकारी बँगले बिहार में भी राजनीतिक टकराव का प्रतीक रहे हैं। सन् 2015 में जब महागठबंधन सत्ता में आया और तेजस्वी यादव उपमुख्यमंत्री बने, तो वे 5 देशरत्न मार्ग के आलीशान रूप से नवीनीकृत बँगले में रहने लगे और उसे उपमुख्यमंत्री का स्थायी आवास घोषित करवाया। लेकिन 2017 के बाद, जब नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया, तो (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

भारतीय संविधान का 9 भाषाओं में अनुवाद जारी किया

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। हर साल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। यह वह ऐतिहासिक दिन है, जब साल 1949 में संविधान सभा ने भारत के संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया था। इसके

- इससे देश के नागरिकों को अपनी भाषा में संविधान को पढ़ने व समझने का मौका मिलेगा।

कुछ अनुछेद 26 नवंबर को लागू कर दिए गए थे। हालांकि, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हुआ, जिसके बाद भारत एक गणराज्य बना। इस साल 2025 में 76वें संविधान दिवस को खास बनाने के लिए केंद्र सरकार एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है।

सरकार द्वारा इस साल संविधान के नौ भारतीय भाषाओं में अनुवाद जारी किये गये। यह पहल देश के नागरिकों (श्रेष्ठ अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

हम यहाँ किसी विशेष कारण से हैं। इसीलिए अपने भूत का कैदी बनना छोड़िये। अपने भविष्य के निर्माता बनिएं। –रोबिन शर्मा

राजस्थान में अनियोजित शहरीकरण: एक नई चुनौती

राजस्थान की धरती सदियों से अपनी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और भौगोलिक विविधता के लिए जानी जाती रही है। मरुस्थल की सादगी और राजमहलों की भव्यता के बीच संतुलित यह प्रदेश अब तेजी से बदल रहा है। विकास की नई परिभाषाएँ यहाँ की जीवनशैली, जनसंख्या के वितरण और पर्यावरणीय ताते-बाने को पुनर्गठित कर रही हैं। पिछले दो दशकों में शहरी विस्तार की जो रफ्तार राजस्थान के शहरों में देखी गई है, वह अभूतपूर्व है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और अलवर जैसे शहर अब छोटे नगरों और गाँवों को अपने भीतर समेटते जा रहे हैं। यह परिवर्तन विकास और रोजगार के अवसर तो ला रहा है, किंतु इसके पीछे छिपे खतरे भी कम नहीं हैं।

राजस्थान परंपरागत रूप से कृषि और पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य रहा है। ठाामीण आबादी यहाँ की रीढ़ रही है, और गाँवों की सामाजिक संरचना से ही इस प्रदेश का सांस्कृतिक स्वर आकार लेता रहा है। लेकिन पिछले पंद्रह-बीस वर्षों में शहरीकरण की गति इतनी तेज हुई है कि ग्रामीण जीवन अब शहर की परिधि में सिमटता जा रहा है। नई औद्योगिक परियोजनाएँ, रियल एस्टेट की बढ़ती माँग, और पर्यटन क्षेत्र का विस्तार ने ग्रामीण भूमि को गिगलान शुरू कर दिया है। परिणामस्वरूप, खेती की जमीनें सिमट रही हैं, और पारंपरिक व्यवसाय भी शहरों पर निर्भर होते जा रहे हैं।

शहरीकरण अपने आप में नकारात्मक नहीं है, लेकिन जब यह अनियोजित और अति-केंद्रित हो जाए, तो कई गंभीर समस्याएँ जन्म लेती हैं। जयपुर इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कभी राजसी सौंदर्य, गुलाबी आभा और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध यह शहर आज यातायात जाम, प्रदूषण, पानी की कमी और बढ़ती जनसंख्या दबाव से जूझ रहा है। जोधपुर और उदयपुर जैसे ऐतिहासिक शहरों में भी इसी प्रवृत्ति के लक्षण दिखने लगे हैं। नगर सीमा के बाहर बसे गाँव अब 'स्माट सिटी' की परिधि में आ रहे हैं, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का टकराव स्पष्ट दिखाई देता है। शहरों का फैलाव केवल भौगोलिक नहीं, सामाजिक रूप से भी हो रहा है—लोगों के जीवन-मूल्य, रिश्तों के स्वरूप और जीवन की गति में व्यापक परिवर्तन दिख रहा है।

अति-शहरीकरण का सबसे बड़ा असर पर्यावरण पर पड़ रहा है। मरुस्थल राज्य होने के नाते राजस्थान सदैव जल संकट से जूझता रहा है। नलकूपों की अंधाधुंध खुदाई, हरियाली के नाम पर अकल्पनीय निर्माण, और भूगर्भीय जल का अनियंत्रित दोहन अब भविष्य के लिए गंभीर चेतावनी बन चुका है। जो शहर कभी जल-संवर्धनशैली थे, वे अब जल के उपभोग पर निर्भर हो गए हैं। जयपुर का उदाहरण लें तो आमेर और जलमहल जैसे तालाब जिनके जल पर कभी पूरा नगर बसता था, अब मात्र पर्यटन स्थल बनकर रह गए हैं। बढ़ते निर्माण कार्य और सड़क विस्तार के चलते वर्षा का पानी जमीन में समाने की बजाय नालों में बह जाता है। इससे भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है।

सामाजिक दृष्टि से देखें तो अति-शहरीकरण ने असमानता को भी जोर दिया है। शहरों में अमीरी और गरीबी के बीच की विभाजक रेखाएँ और गहरी हो रही हैं। एक ओर ऊँची इमारतों में रहने वाले लोगों का जीवन विलासिता से भर है तो दूसरी ओर उन्हीं शहरों के छोर पर झुग्गी-झोपडियाँ बसती जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों से पलायन करने वाले लोग सस्ते श्रम के रूप में इन शहरों की रीढ़ तो बनते हैं, लेकिन उन्हें आधारभूत सुविधाएँ नहीं मिल पाती। पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी सुविधाएँ शहरों के केंद्र तक सीमित हो चुकी हैं।

अति-शहरीकरण का एक और गंभीर पहलू है सांस्कृतिक क्षरण। राजस्थान की पहेलान उसकी लोकसंस्कृति, पोशाक, बोली, संगीत और सामुदायिक जीवन से रही है। लेकिन अब यह सांस्कृतिक धरोहर शहरों के विस्तार में खोती जा रही है। पीढ़ियों से चलने वाले पारंपरिक शिल्प और व्यवसाय अब आधुनिक बाजार व्यवस्था के दबाव में टिक नहीं पा रहे हैं। पारंपरिक मिट्टी के बर्तन, ब्लॉक प्रिंटिंग, कारीगरी या लोकगीतों की जगह अब फैस्ट-फूड-निर्मित उत्पादों और शो-कल्चर ने ले ली है। गाँव का 'मेला' अब मॉल में बदल गया है और साँझ का चबूतरा अब कैफे की टेबल बन गया है। इस बदलाव में सुविधा तो है, पर आत्मीयता नहीं।

राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी अति-शहरीकरण ने नई चुनौतियाँ दी हैं। नगर परिषदों और विकास प्राधिकरणों के पास इतनी तेजी से फैलते शहरों के लिए पर्याप्त योजना और संसाधन नहीं हैं। मास्टर प्लान अक्सर कागज़ों में ही सीमित रह जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य मम्माने ढंग से चलते रहते हैं। भूमि अधिग्रहण और अवैध कॉलोनियों का जाल व्यवस्थित शहरी विकास को बाधित कर रहा है। सरकार को अब ग्रामीण विकास की दिशा में पुनर्विचार करना होगा, ताकि गाँवों को इस शहरी दौड़ में पूरी तरह विस्थापित होने से बचाया जा सके।

अति-शहरीकरण के असर को शिक्षा और युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी चिंताजनक संकेत हैं। गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अवसरों की तलाश में भेजते हैं, लेकिन शहरों की उपभोक्तावादी संस्कृति में उनकी जड़ें कमजोर होती जाती हैं। जीवन का अर्थ केवल आर्थिक उपलब्धियों से जोड़ा जाने लगा है। परिणामस्वरूप सामुदायिक भावना, पर्यावरणीय चेतना और आत्म-संतुलन जैसे मूल्य धीरे-धीरे मुश्किल रहे हैं। परंपरा और आधुनिकता का यह असंतुलन आने वाले समय में सामाजिक विखंडन को जन्म दे सकता है।

राजस्थान के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। विकास आवश्यक है, लेकिन उसका स्वरूप लोक-जीवन के अनुकूल होना चाहिए। शहरों का विस्तार टिकाऊ तभी बन सकता है जब उसमें जल-संरक्षण, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था, और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय हो। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ ताकि लोग केवल बेहतर जीवन की तलाश में शहरों को ओर भागने को विवश न हों। छोटे शहरों पर दबाव कम किया जा सकता है।

राजस्थान के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। विकास आवश्यक है, लेकिन उसका स्वरूप लोक-जीवन के अनुकूल होना चाहिए। शहरों का विस्तार टिकाऊ तभी बन सकता है जब उसमें जल-संरक्षण, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था, और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय हो। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ ताकि लोग केवल बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर भागने को विवश न हों। छोटे शहरों पर दबाव कम किया जा सकता है।

चबूतरा अब कैफे की टेबल बन गया है। इस बदलाव में सुविधा तो है, पर आत्मीयता नहीं।

राजनैतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी अति-शहरीकरण ने नई चुनौतियाँ दी हैं। नगर परिषदों और विकास प्राधिकरणों के पास इतनी तेजी से फैलते शहरों के लिए पर्याप्त योजना और संसाधन नहीं हैं। मास्टर प्लान अक्सर कागज़ों में ही सीमित रह जाते हैं, जबकि जमीनी स्तर पर निर्माण कार्य मम्माने ढंग से चलते रहते हैं। भूमि अधिग्रहण और अवैध कॉलोनियों का जाल व्यवस्थित शहरी विकास को बाधित कर रहा है। सरकार को अब ग्रामीण विकास की दिशा में पुनर्विचार करना होगा, ताकि गाँवों को इस शहरी दौड़ में पूरी तरह विस्थापित होने से बचाया जा सके।

अति-शहरीकरण के असर को शिक्षा और युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ भी चिंताजनक संकेत हैं। गाँवों से शहरों की ओर पलायन करते परिवार अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और अवसरों की तलाश में भेजते हैं, लेकिन शहरों की उपभोक्तावादी संस्कृति में उनकी जड़ें कमजोर होती जाती हैं। जीवन का अर्थ केवल आर्थिक उपलब्धियों से जोड़ा जाने लगा है। परिणामस्वरूप सामुदायिक भावना, पर्यावरणीय चेतना और आत्म-संतुलन जैसे मूल्य धीरे-धीरे मुश्किल रहे हैं। परंपरा और आधुनिकता का यह असंतुलन आने वाले समय में सामाजिक विखंडन को जन्म दे सकता है।

राजस्थान के लिए यह समय आत्मचिंतन का है। विकास आवश्यक है, लेकिन उसका स्वरूप लोक-जीवन के अनुकूल होना चाहिए। शहरों का विस्तार टिकाऊ तभी बन सकता है जब उसमें जल-संरक्षण, हरित क्षेत्र, परिवहन व्यवस्था, और सांस्कृतिक विरासत का समन्वय हो। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ ताकि लोग केवल बेहतर जीवन की तलाश में शहरों को ओर भागने को विवश न हों। छोटे कस्बों को आत्मनिर्भर बनाकर ही बड़े शहरों पर दबाव कम किया जा सकता है।

राजस्थान का भावात्मक और सांस्कृतिक जीवन गाँवों से उभरा है। यदि अति-शहरीकरण की यह नीति इसी रफ्तार से चलती रही तो यह मूल पहचान खोने का खतरा बन सकती है। इस प्रदेश की आत्मा उसकी लोक-संस्कृति में है, जिसे शहरीकरण की चपक में मिटने नहीं देना चाहिए। विकास की दिशा ऐसी हो, जो परंपरा को नष्ट न करे, बल्कि उसे नए युग के साथ जोड़ दे। ऐसा संतुलित दृष्टिकोण ही राजस्थान को एक सशक्त, सुंदर और सतत भविष्य की राह पर ले जा सकता है।

—अतिथि संपादक, अविनाश जोशी,वरिष्ठ पत्रकार एवं कॉर्पोरेट सलाहकार



पंडित अनिल शर्मा

तक, लाभ-अमृत 12:14 से 2:52 तक, शुभ 4:10 से सूर्यास्त तक।
राहुकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:59, सूर्यास्त 5:29 तक

मेघ	सिंह	धनु
 व्यावसायिक/आर्थिक का निपटारा सुविधाएँ के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा।	 विवाहित मामलों का निपटारा सुविधाएँ बढ़ेंगी। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। दिन के मध्याह्न पश्चात परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्ने लगेगे। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष	कन्या	मकर
 नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्य बन्ने लगेगे। धार्मिक-मांगलिक कार्यों में भाग ले सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी।	 मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक कार्य योजनानुसार बन्ने लगेगे। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

मिथुन	तुला	कुंभ
 अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। दिन के मध्याह्न पश्चात अटक हुए कार्य बन्ने लगेगे।	 घर-परिवार में सुख-सुविधाएँ बढ़ेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बन्ने लगेगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। आज स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है। दिन के मध्याह्न पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिलेगी।

कर्क	वृश्चिक	मीन
 परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। दिन के मध्याह्न पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।	 परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा। मित्रों/रिश्तेदारों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।	 आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में उचित सोच-विचार हो सकता है।

एसआईआर-2026: डिजिटल लोकतंत्र की ओर बढ़ते कदम और विरासत का संरक्षण



उत्सव कौशल

मतदाता सूची का शुद्धिकरण केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अस्तित्व का दस्तावेज तैयार करने का महायज्ञ है।

लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति मतदाता है और उसकी सबसे बड़ी पूंजी मतदाता सूची की शुद्धता है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 को यदि हम केवल नाम जोड़ने और हटाने की एक नियमित वार्षिक कवायद भर मानें तो यह इस अभियान के मूल उद्देश्य के साथ

न्याय नहीं होगा। डींग जिले में इस अभियान के क्रियान्वयन के दौरान जो अनुभव सामने आए हैं, वे बताते हैं कि हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ प्रशासनिक दक्षता और जन-भागीदारी मिलकर डिजिटल लोकतंत्र की नींव रख रहे हैं।

अतीत से भविष्य का सेतु :- इस अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इसका ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी नागरिकता, पहचान या वंशवली सिद्ध करने के लिए दशकों पुराने (जैसे वर्ष 2002 या पूर्व के) रेकार्ड खोजते हैं। एसआईआर 2026 आज उसी लिंगेसी डेटा को वर्तमान डिजिटल इकोसिस्टम के साथ जोड़ने का काम कर रहा है।

मैंने कई बार ग्रामीण अंचलों में संवाद के दौरान यह बात दोहराई है कि आज भरा गया आपका एक गणना प्रपत्र केवल वोट देने का अधिकार पत्र नहीं है, बल्कि यह आने वाले 20-30 वर्षों बाद आपकी अगली पीढ़ी के लिए विरासत का प्रमाण बनेगा। जब प्रशासन ने इस दृष्टिकोण को जनता के सामने

रखा, तो लोगों का जुड़ाव भावनात्मक हो गया। यह अभियान अब केवल सरकारी आदेश नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा का प्रश्न बन गया है।

नवाचार: जब प्रतिस्पर्धा बनी प्रेरणा :- एक नवसृजित और ग्रामीण बाहुल्य जिले के रूप में डींग के सामने कई चुनौतियाँ थीं-तकनीकी साक्षरता की कमी, पुराने रिकॉर्ड्स की अनुपलब्धता और प्रवासन लेकिन हमने महसूस किया कि पारंपरिक ढँ से हटकर कुछ नया करना होगा। हमने दंड के बजाय प्रोत्साहन का मॉडल अपनाया। जब हमने प्रतिदिन उत्कृष्ट कार्य करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को बेस्ट बीएलओ के रूप में सम्मानित करना शुरू किया, तो मैदानी अमले में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जग उठी। परिणाम चौकाने वाले थे- 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों पर भी कार्मिकों ने समय से पूर्व 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन का लक्ष्य हासिल कर लिया। यह सिद्ध करता है कि यदि कार्मिकों का मनोबल बढ़ाया जाए और उन्हें स्वामित्व का अहसास कराया जाए तो कठिनतम लक्ष्य भी प्राप्त

किए जा सकते हैं।

कन्वर्जेंस- सिलोस को तोड़ना प्रशासनिक सफलता का मूल मंत्र समन्वय है। निर्वाचन कार्य को अक्सर केवल चुनाव शाखा की जिम्मेदारी मान लिया जाता है, लेकिन हमने इसे कलेक्टिव रिसर्पॉन्सिबिलिटी बनाया। महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बीएलओ के साथ शेंडो वर्कर के रूप में जोड़ना एक निर्णायक कदम साबित हुआ। ग्रामीण परिवेश में जहाँ कई बार पर्दा प्रथा या अन्य सामाजिक कारणों से महिलाओं तक सीधी पहुँच मुश्किल होती है, वहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने घर के भीतर तक पहुंचकर डेटा संकलन को सुगम बनाया। साथ ही, स्कूलों में छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला और रंगोली के माध्यम से अपने अभिभावकों को जागरूक करना-यह दशता है कि जागरूकता अब कक्षाओं से निकलकर चौपालों तक पहुँच चुकी है।

शून्य त्रुटि की प्रतिबद्धता :- एसआईआर-2026 का अंतिम लक्ष्य एक ऐसी मतदाता सूची तैयार करना है

जो त्रुटिहीन हो। दोहरे पंजीकरण और मृत मतदाताओं के नाम हटाना एक बड़ी चुनौती रही है। हमने तकनीक का सहारा लेते हुए स्पष्ट प्रमाण दिया कि डिजिटल प्रणाली अब दोहरी प्रविष्टि को स्वीकार नहीं करेगी। इसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं और लोग स्वयं आगे आकर मतदाता सूची में सुधार करवा रहे हैं।

निष्कर्ष :- विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 केवल आँकड़ों का खेल नहीं है। यह एक पारदर्शी, समावेशी और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया है। डींग जिले में 68इसे अधिक कार्य पूर्ण कर लेना और एक ही दिन में 50,000 से अधिक प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन करना, हमारी प्रशासनिक मशीनरी की बदलती कार्यसंस्कृति का प्रमाण है। यह अभियान सिद्ध करता है कि जब प्रशासन की इच्छाशक्ति और जनता का विश्वास एक साथ मिल जाते हैं, तो लोकतंत्र की जड़ें और गहरी होती हैं।

—उत्सव कौशल (आईएसएस), डींग जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के कारण और समाधान



प्रो. अशोक कुमार

प्रतियोगी परीक्षाएँ योग्यता-आधारित सामाजिक गतिशीलता की आधारशिला हैं। हालाँकि, प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं की बढ़ती संख्या ने इस पूरी प्रणाली की विश्वसनीयता पर एक गहरा संकट उत्पन्न कर दिया है, जो लाखों युवा उम्मीदवारों के भविष्य और सार्वजनिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कमजोर करता है। यह संकट राष्ट्रीय महत्व का हो गया है।

हालिया प्रमुख घटनाएँ और प्रभावित छात्रों का डेटा हाल के वर्षों में लीक की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है, जो इस संकट के विशाल पैमाने को दर्शाती है। 2024 में, कई महत्वपूर्ण भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फरवरी 2024 में, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से लगभग 48 लाख युवा उम्मीदवार प्रभावित हुए। राज्य सरकार को यह परीक्षा रद्द करनी पड़ी और इस चोटाले में शामिल 244 लोगों को निरपेक्ष किया गया। इसी वर्ष, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (उच्चरण) द्वारा आयोजित समीक्षा अधिकारी (RO) और सहायक समीक्षा अधिकारी (ARO) प्रारंभिक परीक्षा की लीक का शिकार हुई, जिसके बाद इसे रद्द किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में अनियमितताओं ने व्यापक चिंता उत्पन्न की। NEET UG 2024 की परीक्षा, जिसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हुए थे, पेपर लीक और ग्रेस मार्क्स विवादों के कारण विवादों में घिर गई। जब परिणाम घोषित हुए, तो 67 छात्रों ने एक साथ शीर्ष रैंक हासिल की, जिससे अनियमितताओं का संदेह पैदा हुआ, और मामले की जाँच सीबीआई को सौंपी गई। इसके अतिरिक्त, जून 2024 के केवल 10 दिनों के भीतर, NEET UG और UGC NET जैसी प्रमुख परीक्षाओं सहित चार बड़ी परीक्षाओं को स्थगित या रद्द करना पड़ा,

जिससे प्रभावित छात्रों की कुल संख्या 38 लाख से अधिक हो गई। यूजीसी-नेट परीक्षा को उसके आयोजन के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया गया, क्योंकि पेपर डाक वेब पर लीक हो गया था। यह निरंतर और बड़े पैमाने पर लीक की घटनाएँ यह दर्शाती हैं कि समस्या अब केवल स्थानीय प्रशासनिक विफलता नहीं है, बल्कि यह केंद्रीय एजेंसियों की परिचालन क्षमता पर राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े करती है। परीक्षा लीक के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव पेपर लीक के प्रभाव केवल परीक्षा रद्द होने तक सीमित नहीं हैं।

बार-बार परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों के मनोबल पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे उनमें लंबे समय तक तनाव और चिंता की स्थिति बनती है। इसके अतिरिक्त, तैयारी, कोचिंग और यात्रा में लगने वाली आर्थिक लागत भी बर्बाद हो जाती है। यह योग्यता-आधारित प्रणाली पर सीधा हमला है; लीक हुए पेपर काथित तौर पर 50,000 रुपये से 2,00,000 रुपये तक की रकम में डेबे जा रहे थे। यदि अयोग्य व्यक्ति उम्मीदवारों या लीक हुए पेपर के माध्यम से प्रशासक बनते हैं, तो यह देश के प्रशासन और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। पेपर लीक के मूल कारण: संस्थागत विफलता और संगठित अपराध पेपर लीक एक जटिल घटना है जो संस्थागत कमजोरियों और संगठित अपराधिक नेटवर्क की बढ़ती ताकत का परिणाम है। संस्थागत और प्रक्रियात्मक कमजोरियाँ परीक्षा प्रणाली की प्रक्रिया श्रृंखला में कई कमजोरियाँ हैं:

सुरक्षा चूक: प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण की पारंपरिक विधि में अक्सर मैनुअल हस्तक्षेप के कई बिंदु शामिल होते हैं, जिन्हें टचपॉइंट्स कहा जाता है। इन बिंदुओं पर सुरक्षा भंग हो सकती है।

लॉजिस्टिक्स में असुरक्षित टचपॉइंट: परिवहन और वेयरहाउसिंग का चरण अक्सर सबसे कमजोर कड़ी साबित होता है। लॉजिस्टिक्स जैसी कोर प्रक्रियाओं को निजी सेवा प्रदाताओं को आउटसोर्स करना एक प्रमुख जोखिम उत्पन्न करता है, क्योंकि ये कंपनियाँ संगठित अपराध के लिए एक आसान प्रवेश द्वार (Entry Point) प्रदान करती हैं।

आंतरिक मिलीभगत: परीक्षा केंद्र स्वयं भी असुरक्षा के बिंदु बन सकते हैं, जहाँ केंद्र के कर्मचारियों की मिलीभगत से रिमोट एक्सेस टूल जैसे माध्यमों से नकल कराई जाती है।

संगठित अपराधिक सिंडिकेट्स की कार्यप्रणाली पेपर लीक अब अत्यधिक संगठित, अंतर-राज्यीय

सिंडिकेट्स द्वारा संचालित होते हैं। उच्च वित्तीय प्रेरणा: सरकारी नौकरियों के प्रति आकर्षण के कारण, पेपर लीक संगठित अपराध के लिए एक उच्च लाभदायक व्यवसाय बन गया है। सिंडिकेट्स कमजोर कड़ी को निशाना बनाते हैं और लाखों रुपये कमाते हैं, जिससे यह एक अरबों रुपये का काला बाजार बन जाता है। डमी उम्मीदवारों का इस्तेमाल: इन सिंडिकेट्स की कार्यप्रणाली में डमी उम्मीदवार (Proxy Candidates) का उपयोग करना एक प्रमुख तरीका है, जो शैक्षणिक रूप से योग्य होते हैं, लेकिन आर्थिक कारणों के कारण मूल उम्मीदवार की जगह परीक्षा में बैठते हैं।

प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग: ये गिरोह नकल के लिए परिष्कृत तकनीकों अपनाते हैं और पूरे परीक्षा चक्र (दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़) को निशाना बनाते हैं। कानूनी और दंडनीय ढाँचा: निवारण के प्रयास पेपर लीक की समस्या से निपटने के लिए, भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने दंडात्मक और नैतिक कानूनों को सख्त किया है। लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024 केंद्र सरकार ने फरवरी 2024 में यह अधिनियम लागू किया, जो उच्चरण, एएन, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और NTA द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को कवर करता है।

अपराध और दंड: सामान्य व्यक्तियों के लिए, न्यूनतम 3 से 5 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना है। संगठित अपराध पर कठोरता: संगठित अपराध करने वाले गिरोहों के लिए 5 से 10 साल तक की कैद और कम से कम 1 करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।

सेवा प्रदाताओं के लिए दंड: यदि कोई सेवा प्रदाता (प्रिंटिंग प्रेस या लॉजिस्टिक्स) दोषी पाया जाता है, तो उस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और उसे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है। राज्य-स्तरीय कानूनों का कठोरता उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक-2024 पेश किया है, जिसमें पेपर लीक करने पर अजीबान कारावास (उघ्रकेंद्र) तक की सजा और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। राजस्थान में भी पेपर लीक के लिए अप्रैक्ट और 10 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है 3.3 दंडात्मक प्रावधानों का कार्यान्वयन कठोर कानून बनाना केवल आधा समाधान है। यदि जांच और अभियोजन की

प्रक्रिया धीमी रहती है (जैसा कि राजस्थान के सख्त कानून में देखा गया है, जहाँ 2022 के कानून के तहत अभी तक किसी को प्रभावी सजा नहीं मिली है), तो कानून केवल कागज़ पर ही मजबूत रहता है। इसलिए, विधायी-कार्यात्मक अंतराल को समाप्त करने के लिए, पेपर लीक के मामलों की तेजी से सुनवाई और निपटान के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करना और जांच/फैसले के लिए 6 महीने की समय सीमा तय करना आवश्यक है। दीर्घकालिक समाधान: संस्थागत अखंडता का रोडमैप पेपर लीक की समस्या का दीर्घकालिक समाधान केवल दंडात्मक कार्रवाई में नहीं, बल्कि संस्थागत अखंडता, प्रशासनिक पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार के रणनीतिक एकीकरण में निहित है।

प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक सुधार NTA का पुनर्गठन और ऑडिट: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) जैसी प्रमुख परीक्षा एजेंसियों में सुधार आवश्यक है। केंद्र सरकार ने सुगोम कोर्ट को बताया है कि NTA के संचालन में सुधार के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें लागू की जाएँगी, जिन्हें परीक्षा प्रक्रियाओं में सुधार और तकनीकी अपग्रेडेशन शामिल है।

सुरक्षा प्रोटोकॉल का मानकीकरण: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल हैंडलिंग को न्यूनतम करना चाहिए। लॉजिस्टिक्स जैसे चरणों को या तो अत्यधिक सुरक्षित सरकारी इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए या निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता कम की जानी चाहिए। सभी कर्मचारियों की गहन प्रष्ठभूमि जाँच अनिवार्य होनी चाहिए। अत्याधुनिक तकनीकी सुरक्षा उपायों का एकीकरण प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग परीक्षा प्रणाली को अपेक्ष बचाने के लिए महत्वपूर्ण है:-

सुरक्षित डिजिटल डिलीवरी:- उन्नत एन्क्रिप्शन (Encryption) और डिजिटल वॉटरमार्किंग का उपयोग किया जाना चाहिए। जस्ट-इन-टाइम डिजिटल डिलीवरी मॉडल अपनाया जा सकता है, जिसके तहत एन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले सुरक्षित सर्वर के माध्यम से केंद्रों को भेजे जाते हैं। यह मुद्रण, भंडारण और परिवहन के दौरान लीक होने के जोखिम को समाप्त कर देता है।

बायोमेट्रिक सत्यापन और AI निगरानी: डमी उम्मीदवारों की समस्या को समाप्त करने के लिए बायोमेट्रिक डेटा (फिंगरप्रिंट) और आधार-

आधारित प्रमाणिकरण का उपयोग किया जाना चाहिए। ऑनलाइन परीक्षाओं में एआई-आधारित रिमोट प्रोक्टरिंग और परीक्षा केंद्रों पर उन्नत सीसीटीवी का उपयोग करके संधिध गतिविधियों की स्वचालित रूप से निगरानी की जा सकती है।

ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग: प्रश्नपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ब्लॉकचेन (Blockchain) तकनीक का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम हो सकता है, जो एक अपरिवर्तनीय (Immutable) लेजर प्रदान करता है, जिस पर प्रश्नपत्र निर्माण से लेकर वितरण तक के प्रत्येक चरण को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

मूल्यांकन प्रणाली में संरचनात्मक सुधार दीर्घकालिक रूप से, शैक्षिक मूल्यांकन में संरचनात्मक सुधार किए जाने चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में पारंपरिक रटने की प्रक्रिया से दूर हटकर योग्यता-आधारित मूल्यांकन (Competence-based assessment) और महत्वपूर्ण सोच (Critical Thinking) पर जोर दिया गया है। यदि परीक्षा और स्वरूप उच्च श्रेणी के कौशल और वैचारिक स्पष्टता की मांग करता है, तो पेपर लीक की वित्तीय प्रेरणा स्वतः ही कम हो जाएगी।

निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें पेपर लीक संस्थानों की योग्यता (meritocracy) पर एक सीधा आवेदन कर देता है, जिससे पब्लिक एजामिनेशन एक्ट, 2024) लागू किया गए हैं। लेकिन ये कानून तभी प्रभावी होंगे जब उन्हें अपेक्ष तकनीकी सुरक्षा उपायों (AI, एन्क्रिप्शन) और मजबूत, ऑडिटेड प्रशासनिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत किया जाए। सरकार को सिस्टम पर निरंतर दबाव बनाना चाहिए कि वह सुनिश्चित करे कि केवल काबिल छात्र ही आगे बढ़ें। न्यायिक और प्रवर्तन तंत्र को सुदृढ़ करके, सिंडिकेट्स का वित्तीय नेटवर्क (मनी ट्रेल) की गहराई से जांच करके और स्वीरित न्याय सुनिश्चित करके ही इस संकट को समाप्त किया जा सकता है। परीक्षा संचालन में पूर्ण पारदर्शिता और निरंतर संचार बनाए रखना भी छात्रों के विश्वास को बहाल करने के लिए आवश्यक है।

—अशोक कुमार, पूर्व कुपणति कानपुर , गोरखपुर विश्वविद्यालय , विभागाध्यक्ष राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

‘आरपीएससी द्वारा शुरू की गई आवेदन विदड्रा सुविधा प्रभावी सिद्ध हो रही है’

अजमेर, (कास)। राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा शुरू की गई आवेदन विदड्रा सुविधा (आवेदन वापस लेने का अधिकार) अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। आयोग के इस दूरदर्शी निर्णय ने न केवल राजकीर्षीय व्यय में उल्लेखनीय कमी की है, बल्कि भर्ती प्रक्रियाओं की गति और पारदर्शिता को भी सुदृढ़ किया है। यह पहल उन अर्थार्थियों को अवसर देने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई, जिन्होंने वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद आवेदन कर दिया था। विदड्रा विकल्प उपलब्ध होने से अब केवल गंभीर और

योग्य अर्थार्थी ही प्रतिस्पर्धा में बने रहते हैं, जिससे परीक्षा आयोजन पर होने वाले अनावश्यक खर्च में भारी कमी आई है। प्रति अप्थर्थी परीक्षा के न्यूनतम औसत जोड़े तो आवेदन वापसी के कारण हुई बचत करोड़ों रुपये तक पहुँच रही है।

आयोग अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने कहा कि अनावश्यक आवेदनों के बोझ से मुक्ति मिलने से आयोग अब योग्य अर्थार्थियों की स्कूटी और अंतिम चयन प्रक्रिया को अधिक तेजी और कुशलता से पूरा कर पा रहा है। उन्होंने इसे पारदर्शी और समयबद्ध

भर्ती तंत्र की दिशा में मील का पत्थर बताते हुए कहा कि अन्य भर्ती संस्थाएँ भी इस नवाचार को अपना रही हैं। अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि वांछित योग्यता न होने के बावजूद आवेदन वापस नहीं लेने वाले अर्थार्थियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में अक्सिस्टेंट प्रोफेसर (संस्कृत कालेज शिक्षा) भर्ती-2024 में योग्यता नहीं होने के बावजूद चेतवानी के बाद भी आवेदन वापस नहीं लेने वाले 14 अर्थार्थियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत सख्त न्यायालय

में परिवार दर्ज करवाया गया है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि यह नवाचार केवल वित्तीय बचत

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : राजस्थान में हाईवे से हटेंगे शराब के ठेके

‘हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने में हटाये जाए’

जोधपुर। राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने हाईवे के 500 मीटर के दायरे में चल रहे सभी 1102 शराब के ठेकों को 2 महीने के भीतर हटाने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते समय सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने म्युनिसिपल एरिया को आड़ में हाईवे को लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर बना दिया है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चाहे ये ठेके नगरपालिका या शहरी सीमा में ही क्यों न आते हों, अगर ये हाईवे पर है, तो इन्हें हटाना ही होगा। यह फैसला प्रदेश में बढ़ते सड़क

■ राजस्थान में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे चल रहे शराब के ठेकों को लेकर हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने ऐतिहासिक और सख्त फैसला सुनाया

■ राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने हाईवे को लिकर-फ्रेंडली कॉरिडोर बना डाला

■ कोर्ट ने हाल ही में जयपुर के हरमाड़ा (15 मौतें) और फलोदी (15 मौतें) में हुए भीषण सड़क हादसों का हवाला देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो रहा है

हादसों और डूंक एंड ड्राइव के मामलों को देखते हुए दिया गया है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए स्वीकार किया कि प्रदेश में कुल 7665 शराब की दुकानों में से 1102 दुकानें नेशनल और स्टेट हाईवे पर हैं। सरकार की

दलील थी कि ये दुकानें आबादी/नगरपालिका क्षेत्र में आती हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की छूट के दायरे में हैं। सरकार ने यह भी बताया कि इन 1102 दुकानों से राज्य को सालाना करीब 2221.78 करोड़ रुपए का भारी-भरकम राजस्व

मिलता है।

हाईकोर्ट ने सरकार की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने तल्ल टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने नगरपालिका क्षेत्र की आड़ में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का मजाक बना दिया है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लोगों की जान की सुरक्षा सर्वोपरि है। 2200 करोड़ रुपए के राजस्व के लिए हम लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। प्रदेश में करीब 7765 शराब की दुकानें हैं। इनसे विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 में 17 हजार 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित हुआ था। यह प्रदेश में किसी सरकारी विभाग में सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। कोर्ट ने बताया कि 2025 में अब तक डूंक एंड ड्राइव के मामलों में करीब 8 प्रतिशत की

बढ़ोतरी हुई है। सितंबर 2025 तक ऐसे 43,788 मामले सामने आ चुके हैं। कोर्ट ने हाल ही में जयपुर के हरमाड़ा (15 मौतें) और फलोदी (15 मौतें) में हुए भीषण सड़क हादसों का हवाला देते हुए कहा कि शराब पीकर गाड़ी चलाना जानलेवा साबित हो रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में 2 दृक निर्देश दिए हैं

500 मीटर का दायरा :- नेशनल या स्टेट हाईवे से 500 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी शराब की दुकान संचालित नहीं होगी। सरकार को ये 1102 दुकानें 2 महीने के भीतर शिफ्ट करनी होंगी। शराब का कोई भी होर्डिंग या विज्ञापन हाईवे से दिखाई नहीं देना चाहिए। अगली सुनवाई 26 जनवरी 2026 को होगी, जिसमें आबकारी आयुक्त को पालना रिपोर्ट पेश करनी होगी।

कोटा : तिलम संघ का जी.एम. तीस हजार रुपये की रिश्मत लेते गिरफ्तार

कोटा, (निर्स)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) बारां की टीम ने बुधवार दोपहर कोटा में बड़ी कार्रवाई करते हुए तिलम संघ के जी.एम. (महाप्रबंधक) रमेश चंद बैरागी को रिश्मत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। तिलम संघ के महाप्रबंधक न्यूनतम समर्थन मूल्य का खरीद केंद्र आवंटित करने की एवज में लाखों रुपए की रिश्मत मांग रहे थे। पहली किस्त के 30 हजार रुपए लेते हुए उन्हें एसीबी की टीम ने पकड़ लिया।

एसीबी बारां के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कालुराम वर्मा ने बताया कि बारां जिले के पलायथा निवासी एक परिवारों ने शिकायत की थी कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद केंद्र संचालित करना चाहते हैं और इसके लिए तिलम संघ में आवेदन किया था। खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद



एसीबी बारां की टीम ने तिलम संघ के महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को रिश्मत लेते गिरफ्तार किया।

बैरागी ने उनसे 1.45 लाख रुपये की रिश्मत मांगी थी। कालुराम वर्मा ने बताया कि मंगलवार को परिवाद का सत्यापन कराया गया जिसमें रिश्मत मांगने की

पुष्टि हुई। इसके बाद बुधवार को ट्रैप टीम गठित की गई। परिवर्दी ने पहली किस्त के रूप में 30 हजार रुपये महाप्रबंधक रमेश चंद बैरागी को

■ तिलम संघ के महाप्रबंधक ने परिवारों से न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद केंद्र आवंटित करने के एवज में 1.45 लाख रुपए की रिश्मत मांगी थी

रावतभाटा रोड़ स्थित तिलम संघ कार्यालय में दिए इसी दौरान एसीबी की टीम ने दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। रिश्मत की राशि भी मौके से बरामद कर ली गई है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपी रमेश चंद बैरागी के ठिकानों पर भी एसीबी की टीम रवाना की गई है, जहां तलाशी और आय से अधिक संपत्ति की जांच की जाएगी।

सेवानिवृत्त अधिकारी को झांसा देकर 9.41 लाख की ठगी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सेवानिवृत्त हुए सहायक अधिकारी को धन दुगुना करने के नाम पर शातिरो ने झांसे में लेकर 9.41 लाख की ठगी कर ली। सायबर ठगी का अहसास होने पर रिटायर्ड अधिकारी ने शिकायत दी तब 1.99 लाख होल्ड करवाए गए, मगर शेष रकम डूब गई। उन्होंने अब महामंदिर थाने में धोखाधड़ी में रिपोर्ट दी है।

जानकारी के अनुसार सी-107 पावटा स्थित धर्मनारायण का हत्या में रहने वाले नवीनचंद्र कौशिक की तरफ से यह रिपोर्ट दी गई है। इन्होंने रिपोर्ट में बताया कि वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (जिला सेशन न्यायालय) से सहायक अधिकारी के रूप में 30 अगस्त 25 को सेवानिवृत्त हुए थे। सरकारी नौकरी में रहते उनके परिलाभ जीपीएफ की राशि 11 लाख रुपए 16 अक्टूबर 25 को खाते में जमा हुई थी। उसी दिन मौलिक नाम के एक शख्स का कॉल आया कि वह गुजरात की कंपनी में मैनेजर पर कार्यरत है और उसकी कंपनी में निवेश के लिए कहा। उसने कहा कि धन निवेश पर एक माह में धन दोगुना कर दिया जाएगा।

इस पर नवीनचंद्र ने उसकी बातों का विश्वास नहीं किया। मगर कुछ रोज बाद में उनके पास में प्रदीपसिंह नाम के शख्स का कॉल आया और कहा कि उसने मौलिक के स्थान पर मैनेजर का पद संभाला है और वह धन दुगुना करने की बात कहने लगा। उसकी बातों में आए सेवानिवृत्त नवीनचंद्र ने 16 अक्टूबर 25 को उसके बताए खाते में 7.5 हजार रुपए निवेश किए, फिर 17 अक्टूबर को 2.50 लाख जमा कराए गए। यह रूपए भदोई की आइडीएफसी शाखा में जमा कराए गए।

बाद में उसने अपने एकाउंटेंट रतनेश गुप्ता के नंबर भी दिए जिस पर अतिता शहा नाम की महिला के खाते में 3.66 लाख रुपए जमा कराए गए। पीड़ित नवीनचंद्र कौशिक ने बताया कि बाद 18 अक्टूबर को जब प्रदीप सिंह को कॉल किया तो उसने फोन नहीं उठाया, फिर उसने कॉल उठाना ही बंद कर दिया। इस पर रिटायर्ड नवीनचंद्र को ठगी का अहसास होने पर उन्होंने पुलिस लाइन पहुंच कर सायबर ठगी की शिकायत दी। इस पर पुलिस ने 1 लाख 99 हजार 818 रुपए होल्ड करवाए, मगर शेष रकम आज तक नहीं मिली। अब उनकी तरफ से महामंदिर थाने में रिपोर्ट दी गई है।

राजस्थान से सिम एक्टिवेट कराकर दूसरे देशों में भेजी, तीन गिरफ्तार

श्रीगंगानगर, (निर्स)। पुलिस ने तीन सायबर ठगी को गिरफ्तार किया है। ये ठग राजस्थान में सिम एक्टिवेट करवाकर साउथ-ईस्ट देशों के ठगी को बेच देते थे। ये आरोपी सायबर ठगी की बैंक में होल्ड पड़ी रकम निकलवाने के भी माहिर थे। फर्जी मोहरे और लेटर पेड बना कर बैंक से होल्ड रकम निकलवा लेते। ये ठगी के रुपयों से चांदी खरीद रहे थे। इनके पास पुलिस को 21 किलो की चांदी और 21 लाख कैश बरामद हुआ है। इस मामले में श्रीगंगानगर में एक मुकदमा एयरटेल कंपनी ने दर्ज कराया, जबकि दो मुकदमे पुलिस से खुद दर्ज किए। एक मुकदमा घड़साना थाने में और एक मटौली राठान थाने में दर्ज हुआ था। बुधवार को एसपी अमृता दुहन ने तीन सायबर ठगी को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया।

एसपी अमृता दुहन ने बताया कि मामले में चंद्र कुमार, संदीप चौहान व दीपक के रूप में पहचान हुई है। तीनों बदमाश श्रीगंगानगर शहर के रहने वाले हैं। इनके पास से 90 चेकबुक, 13 बैंक पासबुक, 64 एटीएम कार्ड, 44 एक्टिव सिम कार्ड, लोगों के आधार, पैन व जन आधार कार्ड, 12 रबर स्टाम्प मोहरे, 23

बिल बुक, लैपटॉप, फर्जी कंपनियों के जीएसटी नंबर व डॉक्यूमेंट बरामद हुए हैं। आरोपियों का बड़ा नेटवर्क है जो लोगों को झांसे में लेकर सायबर ठगी करते थे। इनसे पूछताछ कर नेक्सस की जानकारी जुटाई जा रही है।

एसपी ने बताया कि तीनों आरोपी बैंक अकाउंट को खरीदने और बेचने का काम भी करते थे, जिससे उन्हें बड़ा प्रॉफिट होता था। आरोपियों ने बताया है कि इनका सायबर ठगी करने वाला बड़ा नेटवर्क है। आरोपी गरीब लोगों को ढूंढ कर उनके एटीएम कार्ड, पासबुक, आधार कार्ड, चेकबुक और एक्टिव सिम कार्ड ले लेते थे। जिसके बाद उनके किट बनाकर बड़े सायबर ठगी को प्रोवाइड करते थे। फिर वह ठग बड़े स्तर पर इन गरीबों के बैंक अकाउंट्स में सायबर ठगी के पैसे का लेनदेन करते थे। आरोपी एक व्यक्ति की किट 50 हजार में बेचते थे। लोगों को दो-तीन हजार का प्रलोभन देकर उनके डॉक्यूमेंट ले लिए जाते थे और उनके नाम से सिम एक्टिव करवा ली जाती थी।

एसपी ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपियों ने कुछ बड़े एकाउंट्स के साथ सायबर फ्रॉड भी किया था। जिनके बैंक अकाउंट्स बैंक

ने होल्ड कर दिए थे। इन बैंक अकाउंट्स को होल्ड में से निकलवाने के लिए आरोपियों ने फर्जी मोहर, जीएसटी नंबर और कई प्राइवेट कंपनियों की लेटर पैड बना रखी थी। आरोपी फर्जी लेटर पैड बनाकर बैंक में जाते और होल्ड हुए अकाउंट को एक्टिवेट करा लेते। इसके बाद वह बैंक द्वारा होल्ड किए गए पैसे आसानी से निकलवा लेते।

एसपी ने बताया कि पिछले कुछ समय से साउथ ईस्ट कंट्री (कम्बोडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया) में भारत के सिम एक्टिवेट हो रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे देश में सायबर फ्रॉड हो रहा है। एसपी ने बताया कि जब भी कोई कस्टमर किसी भी कंपनी को सिम लेने जाता है तो एजेंट वैरिफिकेशन के लिए बार-बार ओटीपी और फिंगरप्रिंट लगवाता है। इसके बाद एक बार ही में कई सिम एक्टिवेट हो जाती हैं। कस्टमर को सिर्फ एक ही सिम दी जाती थी और बाकी सिम में अर्जेंट खुद एक्टिवेट कर इन्हें आगे भेज देते थे। जिसके बाद सायबर ठग इन एक्टिवेट सिमों से देश भर में सायबर ठगी करते थे। बिहार पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।

अलग जगह पर वाहन रखे थे। आग शुरूम के अंदर ही लगी और धीरे-धीरे पूरे शोरूम को चपेट में ले लिया। इस बाहर धुआं निकला तब स्थानीय लोगों व राहगीरों ने इसे देखा। एहतियातन पुलिस ने 80 फीट रोड़ पर कुछ दर यातायात को भी बंद रखा। इस शोरूम के ऊपर की तरफ जिम है जिसमें नुकसान नहीं हुआ है। दमकल समय पर पहुंच गई थी इसलिए आग पर काबू पा लिया गया है।

राकेश व्यास ने बताया कि अग्निशमन कर्मचारियों ने पूरी मुस्ती के साथ काम किया। उन्होंने आग को आसपास पहुंचने से रोक़ा। हालांकि पास के ही एक शोरूम में भी आग की लपटें पहुंच गई थी, जिसमें उन्होंने वहां पर खड़े हुए ई-रिक्षा को चपेट में ले लिया। करीब एक दर्जन के आसपास ई-रिक्षा शोरूम करीब 2000 स्क्वायर फीट एरिया में दो मंजिला बना हुआ है जिसमें भूतल पर शोपम की विवरण कुमावत संचालित करते हैं। शोरूम में अलग-

■ एक साथ पहुंची चार फॉयर ब्रिगेड ने आग पर एक घंटे में काबू पा लिया

■ शोरूम में करीब 50 से 60 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक व स्कूटर खड़े थे, आग की चपेट में आ गए

के जरिए लगी है। आगे पूरी कार्रवाई की जा रही है।

फायर एनओसी से लेकर सभी दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। इसके अलावा फॉयर फाईटिंग की क्या व्यवस्था थी इस मामले में भी जांच की जाएगी। राकेश व्यास ने बताया कि यह शोरूम करीब 2000 स्क्वायर फीट एरिया में दो मंजिला बना हुआ है जिसमें भूतल पर शोपम की विवरण कुमावत संचालित करते हैं। शोरूम में अलग-



कोटा में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में भीषण आग लग गई।

आग पूरी तरह से खत्म हो गई। इस शोरूम में करीब 50 से 60 इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक व स्कूटर खड़े थे। सभी आग की चपेट में आ गए। शोरूम में

रखे हुए अधिकांश सामान जलकर राख हो गए।

इस मामले में प्रारंभिक तौर पर सामने आया है कि यह आग शॉर्ट सर्किट

3.20 करोड़ का डोडा-चूरा जब्त, तीन तस्कर गिरफ्तार



आसीद पुलिस ने ट्रक से अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त कर तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

भीलवाड़ा, (निर्स)। जिले के आसीद पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस थाना आसीद ने नेशनल हाईवे 158 पर नाकाबंदी के दौरान एक ट्रक से 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 20 लाख है। इस दौरान पुलिस ने तस्करों में शामिल तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा धर्मेन्द्र सिंह के आदेशानुसार यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सेक्टर सहाड़ा बुधराज खटीक के निर्देशन और पुलिस उप अधीक्षक वृत्त आसीद ओमप्रकाश सोलंकी के सुपरविजन में, थानाधिकारी आसीद हंसपाल सिंह उ.नि. के नेतृत्व में एक टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया।

■ ट्रक से 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम अवैध अफीम डोडा-चूरा जब्त किया

■ ट्रक में ऊपर कपास काकड़ा (कॉटन शीड्स) के कट्टे भरे थे, जिसकी आड़ में नीचे छिपाकर रखे गए अफीम डोडा-चूरा के 103 कट्टे मिले। मानतौल करने पर 21 क्विंटल 29.620 किलोग्राम डोडा चूरा पाया गया, जिसे तस्करों में प्रयुक्त ट्रक सहित जब्त कर लिया गया।

थाना प्रभारी हंसपाल सिंह ने बताया कि पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करों कर रहे तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ कर दिया गया है। पुलिस ने देवेन्द्र पिता मोहनलाल दांडी, पारस पिता चीना राम के साथ बंशीर पिता हमजा खान को गिरफ्तार किया।

कस्बा आसीद में नेशनल हाइवे-

158 पर सवाईभोज पेट्रोल पम्प के पास थानाधिकारी हंसपाल सिंह मय जाप्ता द्वारा नाकाबंदी कर वाहन की रूटोन चेकिंग की जा रही थी। भीलवाड़ा की तरफ से आए एक संदिग्ध ट्रक को रोका गया।

77 ई-मित्र कियोस्क का निरीक्षण

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर में कई जगहों पर ई मित्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के जिला कार्यालय ने 77 ई-मित्र कियोस्क का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनियमितताएँ मिलने पर कई कियोस्क बंद किए गए और संबंधित धारकों पर जुर्माने भी लगाए गए।

संयुक्त निदेशक नवीन माथुर ने बताया कि ओसियां की सुनीता को ई-मित्र धोखाधड़ी में दोषी पाते हुए कियोस्क को स्थायी रूप से बंद करने

की अनुरंसा की गई है। चामू के भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के भर सिंह देवड़ा, महाजन का बास के प्रीति और सवाई किशन राठी, सेखाला बस स्टैंड के कुम्भा राम और जगदीश कुमार के कियोस्क बंद पाए जाने पर जुर्माना लगाया गया।

सेखाला के गड़ा के केवल राम को कियोस्क की गलत जगह के कारण और बावड़ी के राजीव गांधी सेवा केन्द्र के छैल सिंह को सेवा अस्वीकृत पर 1000 रुपये का जुर्माना लगा। श्याम मनोहर नगर चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के

दीपक सैन और जगदीश पर को-ब्राण्ड व आईडी कार्ड नुतिरों के लिए 7 दिन कियोस्क बंद और 5000 रुपये जुर्माना लगाया गया। पाल बालाजी मंदिर के सामने शिवराम चौधरी को आईडी कार्ड, को-ब्राण्ड और अधिक वसूली की अनियमितताओं के लिए 15 दिन कियोस्क बंद और 5000 रुपये का जुर्माना किया गया। बिलाड़ा बस स्टैंड पर घनश्याम पटेल को आईडी कार्ड, सेवा अस्वीकृत, को-ब्राण्ड व अधिक वसूली के लिए 15 दिन कियोस्क बंद रखने का दंड मिला।

कार्यालय जिला कलक्टर, जालोर (राज.)		दिनांक: 26/11/2025
क्रमांक / लेखा/बोली/2025/1286		
निविदा सूचना		
इच्छुक बोलीदाताओं से RRCMS प्रोजेक्ट लागू किये जाने के तहत हाईवेयर क्रय करने हेतु प्रतिष्ठित सदस्यों पंजीकृत फर्मों / व्यवसायियों / डीलरों से खुली बोली दर संविदा हेतु बोलाया दिनांक 05.12.2025 दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित अन्य विवरण राजस्थान लोक उपान मॉर्टल http://sppp.raajasthan.gov.in एवं https://eproc.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।		
UBNC/JS/2526GLOB00026		
अतिरिक्त जालोर		
DIPRC/C/174661/2024		

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सानिवि नगर खण्ड बीकानेर		दिनांक-20/11/2025
क्रमांक-2517		
Notice Inviting Bid: 23/2025-26		
Bid for the Various Civil Works" are invited from interested bidders from 19.11.2025 [09:30 AM to 01.12.2025 [06:00 PM]। Open date 02.12.2025 [11:00 AM], other particulars of the bid may be visited on the procurement portal http://www.pwd.raajasthan.gov.in & http://sppp.raajasthan.gov.in of the state and departmental website. The approximate value of the procurement is Rs. 253.55 Lakh.		
UBN No.: PWD2526WSOB17340, PWD2526WSOB17341, PWD2526WSOB17342, PWD2526WSOB17343, PWD2526WSOB17344		
Executive Engineer PWD City Division, Bikaner		
DIPRC/C/17298/2024		

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	
ई-बोली आमन्त्रण सूचना	
इच्छुक बोली दाताओं से 36 केबी क्वंट ट्रांसफार्मर (0.25 वोल्ट) के विभिन्न अनुपात और 36 kV पोर्टेबिलिटी ट्रांसफार्मर (0.2 वोल्ट) (बीएन-9015002521 यूवीएन - VPN2526GLRC02279) की खरीद हेतु ऑनलाइन बोली आमंत्रित की जाती है। विस्तृत जानकारी और बोली दस्तावेज / विनिर्देश वेबसाइट http://eproc.raajasthan.gov.in पर देखने एवं डाउनलोड करने हेतु उपलब्ध है। एनआरबी का विवरण वेबसाइट energy.raajasthan.gov.in/rvnp पर उपलब्ध है। बोली खोलने की तिथि में संशोधन की सूचना http://eproc.raajasthan.gov.in (energy.raajasthan.gov.in/rvnp) पर http://sppp.raajasthan.gov.in पर ही प्रकाशित की जाएगी। रा.रा.वि.प्र.नि. / TR-7263/2025 राज.संवाद / सी / 25 / 14650	
अधीक्षण अभियन्ता (क्रय-1)	

कार्यालय नगर परिषद्, ब्यावर

Tel No. 01462-258665, 257509

Email - npbsewar@gmail.com

क्रमांक / न.प.या. / भा/डा / 2025-26 / 9528

दिनांक 18.11.2025

ई-दर संविदा सूचना

निम्नांकित विवरणानुसार दिनांक 01.12.2025 को प्रातः 11:00 बजे तक ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान पर सेवाओं का उपान हेतु ई दर संविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। ई-दर संविदा फार्म ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान तथा एसपीपी पोर्टल राजस्थान से डाउनलोड कर उपयोग में लेने हैं। कार्यालय से फार्म विक्रय नहीं किये जावेंगे। विस्तृत शर्त ई-दर संविदा फार्म में संलग्न है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	घरोहर राशि	ई दर संविदा फार्म शुल्क	ई दर संविदा प्रोसेसिंग शुल्क
1	Scanning and digitization work of Municipal Records	40,00,000	80।000	1000	500

NIB - DLB2526A8216

UBN - DLB2526SLOB24600

प्रशासक

आयुक्त

नगर परिषद्, ब्यावर

नगर परिषद्, ब्यावर

राज.संवाद / सी / 25 / 14640

Visit Us: www.mput.ac.in ; Mail Id: zdr_arb@yahoo.com ; Mo. No: 8112207969।94।4389929	
कृषि अनुसंधान केन्द्र, दाहोद रोड, बोरवट फार्म, बांसवाड़ा (राज.) 327 001 (महाराजा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर)	
क्रमांक: एक()क/अके/2025-26/203-206	दिनांक: 24/11/2025

निविदा सूचना (2025-26)

कृषि अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा, के लिये कृषि कार्य हेतु पंजीकृत संवेदक / ठेकेदार से अपेक्षित अनुभव क्षमताओं के साथ मासिक कार्य/कार्यानुसार हेतु खुली निविदाएं बंद लिफाफों में आमंत्रित की जाती है। पंजीकृत संवेदक / ठेकेदारों को तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग सील बन्द लिफाफों में देनी होगी। निविदा प्रारूप, सम्पूर्ण नियम एवं शर्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mput.ac.in एवं [www.sppp.raajasthan.gov.in](http://sppp.raajasthan.gov.in) से डाउनलोड कर सकते हैं। निविदा प्रारूप प्राप्ति की अन्तिम तिथि 03.12.25 प्रातः 11.00 बजे तक रहेगी। उक्त निविदाएं उसी दिन दोपहर 11.30 बजे तक जमा की जाकर मूल्यान 12.00 बजे कमेटी की उपस्थिति में खोली जावेगी। निविदा प्रारूप जमा करवाते समय कार्य के सामने वर्णित निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा करवानी होगी।

कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (₹.)	घरोहर राशि (₹.)	निविदा शुल्क (₹.)
फल अनुसंधान केन्द्र, बांसवाड़ा एवं CAMESA Project में कृषि कार्य	3,92,200 / -	8000 / -	500 / -

संभागीय निदेशक अनुसंधान

सरदार पटेल से प्रेरणा लेकर ‘राष्ट्र प्रथम’ को सर्वोपरि रखें युवा : भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री ने अमर जवान ज्योति से यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाई

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शी सोच, दृढ़ इच्छाशक्ति और साहसिक निर्णयों से भारत को एकजुट कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि युवा सरदार पटेल के जीवन से प्रेरणा लेकर ‘राष्ट्र प्रथम’ को सर्वोपरि रखें तथा एक मजबूत, एकजुट तथा विकसित भारत के निर्माण में योगदान दें। शर्मा ने सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर ने विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमें दिया है तथा उसी आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। शर्मा ने बुधवार को अमर जवान ज्योति से सरदार 150 यूनिटी मार्च के अंतर्गत यमुना प्रवाह यात्रा के तहत आयोजित समारोह को संबोधित किया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देशभर में सरदार पटेल की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी के तहत यमुना प्रवाह यात्रा भी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के तहत राजस्थान सहित विभिन्न प्रदेशों से युवा जयपुर से सरदार पटेल की जन्मभूमि कमरसद तक की यात्रा करेंगे। यह यात्रा युवाओं के लिए सरदार पटेल के जीवन, संघर्ष और देशभक्ति को



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति से यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

करीब से जानने का अवसर है। साथ ही, युवाओं को सरदार पटेल के आदर्श और मूल्यों को समझने का प्रत्यक्ष अनुभव भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरदार पटेल का स्वतंत्रता आंदोलन में अमूल्य योगदान रहा। बारडोली सत्याग्रह में उनकी प्रभावशाली भूमिका के कारण उन्हें सरदार की उपाधि दी गई।

उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भी बड़-चढ़कर भाग लिया और किसानों को अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया और सरदार पटेल जेल भी गए। लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया।

शर्मा ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी तो मिली लेकिन विभाजन का दर्द भी सहना पड़ा। उस समय देश सैकड़ों टुकड़ों में बंटा हुआ था। उन्होंने कहा कि देश की 562 रियासतें स्वतंत्र इकाई थीं। सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति, दूरदर्शिता और कभी-कभी कठोरता का इस्तेमाल करते हुए प्रत्येक रियासत को भारत में मिलाना शुरू किया।

उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद तथा जनमत संग्रह कराकर जुनागढ़ को भारत में शामिल कराया। उन्होंने भारत की एकता और अखंडता को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बनाया और

उसे पूरा करके दिखाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल की विरासत को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। सरदार पटेल का अधूरा सपना प्रधानमंत्री ने कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया। प्रधानमंत्री भारत को एक सूत्र में बांध रहे हैं।

पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक आज भारत एक हो रहा है। सरदार पटेल के योगदान को सम्मान देते हुए विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश में गरीब कल्याण, विकास योजनाओं, आतंकवाद-नक्सलवाद

■ लौह पुरुष ने दूरदर्शी सोच और साहसिक निर्णयों से देश को किया एकजुट : सीएम

का खात्मा तथा विश्व पटल पर देश का सम्मान बढ़ने जैसे अभूतपूर्व कार्य हुए हैं।

उन्होंने कहा कि पूरा विश्व भारत को उम्मीदों से देख रहा है तथा दुनिया के सबसे बड़े लीडर के नेतृत्व में देश नई ऊंचाईयां छू रहा है।

शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल का जीवन युवाओं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। युवा पीढ़ी उनके जीवन से कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, दृढ़ संकल्प, एकता तथा सादगी की पांच प्रमुख सीख ले सकती है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सरदार 150 यूनिटी मार्च के तहत यमुना प्रवाह यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले शर्मा ने अमर जवान ज्योति पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को नमन भी किया। इस दौरान सांसद मदन राठीड़, मंजू शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ, जितेन्द्र गोठवाल, गोपाल शर्मा, बालमुकुन्दाचार्य सहित बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे।

10 दिव्यांगों को मिलेगा सम्मान

जयपुर। विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को भारतीय दिव्यांग संघ की ओर से जवाहर कला केंद्र स्थित रांगयन सभागार में दिव्यांगों से जुड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

कार्यक्रम में देशभर से दिव्यांगजन अपनी कला, प्रतिभा और दक्षता को दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। मुख्य अतिथि राज्यपाल हरीभाऊ किशनराव बागडे होंगे।भारतीय दिव्यांग संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद नारायण और राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार देवेन्द्र कुमार शर्मा ने यह जानकारी दी।

एसबीए ग्रुप ने “हडल” का शुभारंभ किया

भारतीय व्यवसायों को वैश्विक उद्यमों में परिवर्तित करने के लिए प्रमुख सहयोगी कार्यस्थल



राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने एसबीए ग्रुप के “हडल” का उद्घाटन किया। उनके साथ सांसद मंजू शर्मा भी मौजूद थीं।

जयपुर। सात दशकों की अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक विशेषज्ञता वाली अग्रणी परामर्श फर्म एसबीए ने बुधवार को “हडल” का उद्घाटन किया, जो भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया एक अत्याधुनिक सहयोगी कार्यस्थल है। इसका कार्यालय 10वीं मंजिल, सिग्मेचर एलीट जे-7, गोविंद मार्ग जयपुर में है।

मुख्य अतिथि विधानसभाध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि हडल भारतीय व्यवसायों के बहुराष्ट्रीय संचालन में विस्तार के लिए आधार तैयार करेगा। यह पहल राजस्थान सरकार की राज्िगं राजस्थान दृष्टि में पहला ठोस कदम है। ऐसी परिyoजनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत पहल को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। एसबीए के अध्यक्ष ने हडल को रणनीतिक दृष्टि को भारत भर में स्टार्टअप और विकास चरण के व्यवसायों के लिए एक व्यापक इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में व्यक्त किया। हडल उद्यमियों को प्रौद्योगिकी-सक्षम सेवाओं के साथ इष्टतम आराम प्रदान करता है। एसबीए की वैश्विक उपस्थिति का लाभ उठाते हुए, हम जयपुर के केंद्र से व्यवसायों को विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के साथ फलने-फूलने में सक्षम बनाते हैं।

एसबीए ग्रुप के सीईओ अर्पित भार्गव और सीओओ राधिका शर्मा ने हडल को जयपुर और राजस्थान में बढ़ते

व्यवसायों के लिए लॉन्चपैड बताया। एसबीए कंपनियों को एक ही छत के नीचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित सलाह प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों की सत्तर वर्षों की सेवा पर निर्मित, एसबीए ने एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाया है जो परामर्श, प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे और पेशेवर सलाहकार सेवाओं को एकजुट करता है। समारोह में स्वर्गीय सीए वी.एन. भार्गव, एसबीए के सह-संस्थापक के सम्मान में विश्वेश्वर सभागार का समर्पण किया गया। समारोह में सांसद मंजू शर्मा, मंत्री गौतम कुमार दक और कन्हैया लाल ने पहल की प्रशंसा की और इस परिवर्तनकारी सहयोगी स्थान के लिए एसबीए को बधाई दी।

‘गवाही तक जांच अधिकारी का रोके वेतन’

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने चंदवाजी थाने में दर्ज आपराधिक मामले में जांच अधिकारी के निचली अदालत में गवाही के लिए नहीं जाने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी उदय सिंह दूसरे कामों में व्यस्तता का हवाला देकर निचली अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं। यह गवाही से बचने का प्रयास है

और अभियोजन पक्ष गवाह पेश करने में विफल रहा है। इसके साथ ही अदालत ने पुलिस महानिदेशक और कोषाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जब तक अनुसंधान अधिकारी गवाही के लिए दायरत कोर्ट में हाजिर नहीं हो या अदालत उन्हें राहत नहीं दे, तब तक उसका वेतन और अन्य भत्ते रोक लिए जाए।

राजस्थान विधानसभा में “वंदे मातरम् दीर्घा” का उद्घाटन



जयपुर (कासं)। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि देश का संविधान सुरक्षित है। इसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि संविधान भारत की आत्मा, भविष्य और वर्तमान है। दुनिया में भारत का संविधान ही ऐसा मजबूत संविधान है जिसके माध्यम से सत्ता का हस्तान्तरण शांतिपूर्ण तरीके से होता है। भारतीय संविधान की यह सबसे बड़ी विशेषता है।

देवनानी ने कहा कि वन्दे मातरम् केवल गीत ही नहीं है, यह मातृभूमि के प्रति समर्पण, औपनिवेशिक दमन के विरुध प्रतिरोध और स्वाधीनता की सामूहिक चेतना का प्रभावी प्रतीक है। समय के साथ यह गीत जन सभाओं और सांस्कृतिक आयोजनों में भारत के स्वतन्त्रता संग्राम की प्रेरणा शक्ति बन गया है।

देवनानी ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का शुभारम्भ किया। देवनानी ने इस मौके पर विधान सभा के डिजिटल म्यूजियम में उनकी पहल से निर्मित वंदे मातरम दीर्घा का उद्घाटन किया। देश की विधान सभाओं में राजस्थान विधान सभा कदाचित ऐसी विधान सभा बन गई है, जहाँ वंदे मातरम् दीर्घा का निर्माण किया गया है। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी

की सोच व परिकल्पना के अनुरूप राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के ऐतिहासिक पहलुओं को चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। देवनानी ने कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्र है तो हम हैं। देश के प्रति विश्वास और श्रद्धा रखो। देश के लिए जिए। अधिकारों को मांगे लेकिन कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व से भी मुँह ना मोड़ो। पूरी क्षमता के साथ राष्ट्र हित का कार्य करो। भारत विश्व की महान शक्ति है। भारत विश्व गुरु है। यह सब भारतीय संविधान के कारण ही सम्भव है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि संविधान की मूल भावना में न्याय है। न्याय सभी को मिले। न्याय व्यवस्था में विश्वास करें। इसका स्वयं पालन करें और फिर दूसरों को

कहे। समारोह में मौजूद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि संविधान की मजबूती बनाने की जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की है। अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल ने कहा कि संविधान राष्ट्र के लोगों की भावना है। स्पीकर देवनानी ने बताया कि 47 पैनलों के माध्यम से वंदे मातरम् के इतिहास और इससे सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारीयों का दीर्घा में समावेश किया गया है। उन्होंने कहा कि सन् 1875 में अक्षय नवमी के दिन वंदे मातरम् की रचना, बंकिमचन्द्र ने इसे पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के लालगोला में लिखा, संस्कृतनिष्ठ बंगाली में लिखे गए मूल गीत के चित्र सहित विभिन्न जानकारीयां आमजन, युवा, शोधार्थी और छात्र-

छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। देवनानी ने बताया कि राजस्थान विधानसभा स्थित राजनैतिक आख्यान संग्रहालय में वंदे मातरम् दीर्घा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना के इतिहास को नई दृष्टि से प्रस्तुत करने वाली एक प्रेरणादायी पहल है। दीर्घा बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित ‘वंदे मातरम्’ की मूल भावना को केंद्र में रखते हुए स्वदेशी आंदोलन, जन-आंदोलनों तथा क्रांतिकारियों की भूमिका को सजीव रूप में दर्शाती प्रतीत हो रही है। दीर्घा में गीत की मूल पंक्तियों, पांडुलिपि की प्रतिकृति और उस समय के राजनीतिक-सांस्कृतिक परिवेश का सुव्यवस्थित प्रदर्शन किया गया है। इससे आगंतुकों को स्वतंत्रता संग्राम के दौर की भावनाओं का अनुभव हो सकेगा। वंदे मातरम् के भावपूर्ण संगीत तथा आंदोलन से जुड़े दुर्लभ फोटोग्राफ़, पत्र, भाषण और वीडियो सामग्री भी दीर्घा में शामिल की गई है।

विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधान सभा के राजनैतिक आख्यान संग्रहालय के प्रवेश पथ को राजस्थान की कला, संस्कृति के अनुरूप भित्ति चित्रों के माध्यम से नये सिरे से तैयार कराया है। राजस्थान के महापुरुष, कलाकृतियाँ, लोक कला, लोक नृत्य, राष्ट्रीय पक्षी, राज्य पशु के साथ यहां के पारंपरिक हाथी, घोड़े सहित राज्य की कला और संस्कृति को समेटे हुये भित्ति चित्रों के माध्यम से प्रवेश पथ को बनाया गया है।

2 साल में राजस्थान ने जोड़ी 1 9 हजार मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता : हीरालाल नागर

जयपुर (कासं)। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बुधवार को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में दो दिवसीय लोबल सोलर एक्सपो-2025 का उद्घाटन किया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप राजस्थान आज अक्षय एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता बढ़कर 35 हजार 357 मेगावाट तक पहुंच गई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीते लगभग दो वर्षों में इस क्षमता में

करीब 19 हजार मेगावाट की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2070 तक देश को नेट-जीरो के लक्ष्य की दिशा में राजस्थान पूर्ण प्रतिबद्धता से आगे बढ़ रहा है।

नागर ने कहा कि पीएम कुसुम योजना ने किसानों को अन्नदाता के साथ-साथ ऊर्जादाता भी बनाया है। प्रदेश में इस योजना के तहत लगभग 2400 मेगावाट क्षमता के विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हो चुके हैं, जिससे किसानों को दिन में भी कृषि कार्यों हेतु सस्ती एवं निर्बाध बिजली

उपलब्ध हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प के अनुरूप वर्ष 2030 तक देश में 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। इसी दिशा में राज्य सरकार पूरी तरह समर्पित है। प्रमुख शासन सचिव, ऊर्जा विभाग अजिताभ शर्मा ने कहा कि कुसुम योजना के कम्पौनेट-ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि कम्पौनेट-सी में गुजरात और महाराष्ट्र के बाद तीसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा की असंमित संभावनाओं को देखते हुए केंद्र

एवं राज्य सरकार दोनों का उद्देश्य नवीन नीतियों एवं नवाचार के माध्यम से प्रदेश में सौर उत्पादन के साथ-साथ भंडारण क्षमता का भी विकास करना है। नागर ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और विभिन्न सोलर कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे नवीन एवं अत्याधुनिक सौर उत्पादों की जानकारी ली। इस अवसर पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता, इंटरनेशनल के सीईओ आनंद गुप्ता, सौर ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आगंतुक उपस्थित थे।

राज्य में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और आपूर्ति : डॉ. किरोडी लाल

प्रदेश में वर्तमान में 1.84 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 65 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 64 हजार मैट्रिक टन एनपीके एवं 1.53 लाख मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध

जयपुर (कासं)। कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल ने बुधवार को राज्य में कृषकों को उर्वरकों की आपूर्ति एवं आवश्यकता अनुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और कृषि विभाग द्वारा उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कम उपलब्धता और अधिक खपत वाले जिलों व ब्लॉकों को चिन्हित कर प्रदेश भर में प्राथमिकता के साथ पूर्ण पारदर्शिता से उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। उर्वरकों की कालाबाजारी व जमाखोरी रोकने के लिए विभागीय अधिकारी प्रदेश भर में पूर्ण सतर्कता से कार्य कर रहे हैं।

कृषि मंत्री डॉ. किरोडी लाल मीणा ने बताया कि राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रबी 2025 में अक्टूबर व नवम्बर में भारत सरकार द्वारा आवंटित 1 लाख 55 हजार मैट्रिक टन यूरिया के विरुद्ध 01 अक्टूबर 2025 को उपलब्ध स्टॉक सहित अब तक 8 लाख 99 हजार मैट्रिक टन की उपलब्धता की गई है एवं 35 हजार मैट्रिक टन यूरिया परिवहन में है, जिसकी आपूर्ति आगामी 2 दिवसों में हो जायेगी।

■ 35 हजार मैट्रिक टन यूरिया परिवहन में है, प्रदेश में फिलहाल राज्य की मांग से अधिक उर्वरकों की उपलब्धता है।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1 लाख 84 हजार मैट्रिक टन यूरिया, 65 हजार मैट्रिक टन डीएपी, 64 हजार मैट्रिक टन एनपीके एवं 1 लाख 53 हजार मैट्रिक टन एसएसपी उर्वरकों का स्टॉक उपलब्ध है।

वर्तमान में गत वर्ष की तुलना में फॉस्फेटिक उर्वरकों का स्टॉक 69 हजार मैट्रिक टन अधिक है। केंद्र सरकार की ओर से यूरिया, डीएपी एवं अन्य उर्वरकों का राज्यो को माहवार व कमपनीवार आवंटन किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त आवंटन एवं जिलों की मांग के अनुसार जिलेवार आपूर्ति योजना तैयार कर प्रदेश में उर्वरकों का वितरण पारदर्शिता से कराया जा रहा है।

प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी मंजू राजपाल ने बताया कि कृषकों को मुद्रा स्वास्थ्य काई में अंकित सिफारिशानुसार ही उर्वरकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने, उर्वरकों का समान रूप

से पारदर्शिता के साथ वितरण कराने और उर्वरक वितरण में अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं, जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

राजपाल ने बताया कि विभाग द्वारा राज्य में प्रत्येक उर्वरक विक्रेता के विक्रय परिसर पर उर्वरकों का वितरण व प्रभावी मोनेटरिंग किये जाने हेतु विभागीय अधिकारियों, कार्मिकों की नामजद ड्यूटी लगायी गई है। किसी विक्रेता के यहां कृषकों की संख्या अधिक होने पर कृषकों को पंक्तिबद्ध किया जाकर उनकी देख-रेख में उर्वरकों का वितरण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया गया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से उर्वरकों का अन्य राज्यों में परिगमन रोकने हेतु विभागीय कार्मिक एवं आवश्यकतानुसार पुलिस के सहयोग से 61 चैक पोस्ट स्थापित किये गये हैं, जिनके द्वारा नियमित निगरानी जारी है।

समय-समय पर विशेष अभियान चला कर उर्वरक वितरण में जमाखोरी, कालाबाजारी, यूरिया डायवर्जन सहित अन्य अनियमितता बरतने वाले विक्रेताओं के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की गई है।

लो फ्लोर बस चालकों की हड़ताल समाप्त

जयपुर। जेसीटीसीएल,बगराना डिपो की लो –फ्लोर बस चालकों की दो दिन से चल रही हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई। लो फ्लोर बसों का संचालन करने वाली निजी फर्म पारस ट्रेवलस ने ड्राइवर यूनियन की 5 मांगों को लेकर सहश्रति बन गई।

इससे पहले बुधवार को बगराना डिपो के बाहर बस चालकों ने जमकर विरोध- प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि पारस ट्रेवलस फर्म लगातार श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। ड्राइवरों को मेटेनैस के बिना खराब बसें चलाने को मजबूर किया जाता है। जिससे हादसे का खतरा बढ़ता है। बीते दिनों टोंक फाटक पुलिस पर बस में लगी आग और पिछले दिनों में हुए कई हादसे इसी लापरवाही का नतीजा है। जिसके बाद पांच सूत्रीय मांगों को मान लिया गया। लो –फ्लोर बस चालकों ने दुर्घटना में मारे गए लो –फ्लोर बस चालक कुलदीप मीणा के परिवार को आर्थिक सहायता, ड्यूटी के दौरान लकवा ग्रस्त करने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि दो दिन पहले लो –फ्लोर बस चालकों ने पांच सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर दी थी।

कस्टोडियन भूमि के वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत अधिकार दिलाने की पहल तेज

विधायक यूनस ख़ान के नेतृत्व में सामूहिक प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन

डीडवाना, (निसं)। विधानसभा क्षेत्र के विधायक यूनस खान ने शासन सिचवालय जयपुर में मुख्य सचिव राजस्थान वी. श्रीनिवास तथा शासन सचिव, राजस्व एवं उपनिवेश विभाग, डॉ. जोगाराम से मुलाकात कर उपखण्ड डीडवाना की निष्क्रान्त (कस्टोडियन) भूमि पर बसे वास्तविक कब्जाधारियों को विधिसम्मत नियमन, आवंटन एवं नामान्तरकरण प्रदान करने से संबंधित विस्तृत ज्ञापन सौंपा। इस प्रतिनिधिमंडल में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीणजन भी उपस्थित रहे।

विधायक यूनस खान ने मुलाकात के दौरान बताया कि डीडवाना के शहरी एवम् ग्रामीण अंचलों में सैकड़ों परिवार पिछले कई दशकों से कस्टोडियन दर्ज भूमि पर निवास और कृषि कार्य कर रहे हैं, किंतु उन्हें अब तक कानूनी स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नहीं हो सका है। उन्होंने कहा कि इन परिवारों ने स्वतंत्रता के बाद कठिन परिस्थितियों में घर बनाए, भूमि को उपजाऊ बनाया, व्यवस्थित रूप से कर अदा किए और सामाजिक रूप से स्वयं को स्थापित किया, फिर भी राजस्व

- कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे पात्र परिवारों को राहत दिलाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी सरकार : मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास**

अभिलेखों में भूमि कस्टोडियन के रूप में दर्ज रहने के कारण आज वे कानूनी अनिश्चितता और असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से ऐसे परिवारों को उनका वास्तविक और विधिसम्मत अधिकार दिलाने के लिए त्वरित एवं ठोस कार्रवाई करने का आग्रह किया।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए आश्वस्त किया कि डीडवाना-कुचामन जिला कलेक्टर को आवश्यक दिशा-निर्देश शीघ्र जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी और कस्टोडियन भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे पात्र परिवारों को राहत दिलाने के लिए सकारात्मक कदम उठाएगी।

शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने भी विस्तृत चर्चा में बताया कि विभाग कस्टोडियन भूमि संबंधी प्रकरणों के

व्यवस्थित निस्तारण के लिए विशेष समीक्षा प्रक्रिया प्रारंभ करने पर विचार कर रहा है, तथा डीडवाना क्षेत्र जैसे प्रभावित इलाकों में जिला स्तरीय समिति गठित कर सर्वे व सत्यापन कार्य तेज किए जाएंगे। उन्होंने नियमन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल और समयबद्ध बनाने की दिशा में भी आश्वानन दिया।

जापन के साथ विधायक यूनस खान ने निष्क्रान्त संपत्ति की ऐतिहासिक एवं कानूनी पृष्ठभूमि का उल्लेख करते हुए बताया कि वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान पाकिस्तान गए परिवारों की संपत्तियों को भारत सरकार ने ‘निष्क्रान्त संपत्ति’ घोषित कर कस्टोडियन विभाग को सुपुर्द किया था। इसके बाद राजस्थान सरकार ने 1963 और 197० के भू-राजस्व नियमों में इनके स्थायी आवंटन के लिए प्रावधान किए। भारत सरकार के कैबिनेट निर्णय 69/

2008 के अनुसार अप्रयुक्त निष्क्रान्त भूमि को ‘सिवायचक’ दर्ज करने के निर्देश दिए गए, जिनके अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2००9 में जारी आदेशों के अनुसार इन भूमियों को सिवायचक में दर्ज किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने शामिल ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों ने विधायक यूनस खान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों से लंबित इस गंभीर समस्या को सरकार के सर्वोच्च स्तर पर मजबूती से उठाकर प्रभावित परिवारों के लिए आशा की किरण जगाई है। उन्होंने कहा कि विधायक के प्रयासों से अब कस्टोडियन भूमि विवाद के स्थायी समाधान का मार्ग प्रशस्त होने की वास्तविक संभावनाएं बनी हैं।

अंत में विधायक यूनस खान ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन मिलकर इस विषय पर शीघ्र, पारदर्शी और मानवीय समाधान सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक डीडवाना क्षेत्र के प्रत्येक पात्र परिवार को उनका विधिसम्मत अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह प्रयास लगातार जारी रहेगा।

अवैध बजरी खनन का स्टॉक जब्त, दो गिरफ्तार



बौली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन स्टॉक जब्त कर दो चालकों को गिरफ्तार किया।

बौली-बामनवास, (निसं)। सर्वाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध बजरी खनन व स्टॉक पर कार्रवाई करते हुए बौली थाना पुलिस ने एक लोडर, एक पिकअप केन्द्रा व आठ टन बजरी स्टॉक को जब्त कर दो चालकों को गिरफ्तार किया है।

बौली सर्किल इस्पेक्टर जितेंद्र सिंह सोलंकी के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हैड कांस्टेबल जयदेव सिंह ने मय टीम के 8 लाइन दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे टोलटेक्स बौली के पास खाली जगह में अवैध बजरी स्टॉक कर बजरी को लोडर की सहायता से भरते हुए एक लोडर व एक पिकअप कैन्ट्रा व 8० टन अवैध बजरी

के स्टॉक को जब्त कर लोडर चालक मुकून गुर्जर निवासी गुडला नदी व मुरारी लाल मीणा पिकअप केंद्रा चालक निवासी झनूण को गिरफ्तार किया। सक्रिल इस्पेक्टर जितेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों ने

- एक लोडर, एक पिकअप केन्द्रा व आठ टन बजरी स्टॉक जब्त**

बताया कि ये साधन लोडर व पिकअप केंद्रा प्रवीण गोयल निवासी बौली के पत्र पर हैं, गोपनीय जानकारी मिली कि प्रवीण द्वारा 8 लाइन एक्सप्रेस-वे के पास खाली पड़ी जमीन में टोलकर्मों फिरोज गद्दी निवासी भारजा नदी थाना मलारना ड्रंगर द्वारा चोरी छुपे अवैध बजरी का स्टॉक करवाया जाता था एवं अवैध बजरी के स्टॉक को लालसोट बड़ का पाड़ा, ममात लालसोत में बेचा जा रहा है।

इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चालक मुकून गुर्जर व मुरारी लाल मीणा को मौके से गिरफ्तार कर लिया एवं अन्य आरोपी प्रवीण गोयल व टोलकर्मों फिरोज गद्दी निवासी भारजा नदी थाना मलारना ड्रंगर की तलाश जारी है।

संविधान दिवस पर गोष्ठी आयोजित

बूंदी, (निसं)। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को कृषि विज्ञान केंद्र में गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें केन्द्र के कीट वैज्ञानिक प्रोफेसर हरीश वर्मा ने संविधान उद्देशिका का वाचन किया।

उन्होंने बताया कि संविधान दिवस का उद्देश्य संविधान की सोच, संवैधानिक सिद्धांतों और नागरिक कतव्यों के प्रति जन-जागरुकता बढ़ाना है। संविधान केवल सरकार का ढांचा तय नहीं करता, बल्कि नागरिकों के अधिकारों, स्वतंत्रताओं और गरिमा की भी रक्षा करता है। यह दिवस हमें लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने और संवैधानिक मूल्यों को जीवन का हिस्सा बनाने की प्रेरणा देता है। संविधान दिवस हमें यह सीख देता है कि भले ही लोकतंत्र मतभेद से बनता है, परन्तु हमारा देश जागरुकता, कतव्यपरायणता और संवैधानिक मूल्यों से चलता है। इस दौरान केन्द्र के फार्म मैनेजर महेन्द्र चौधरी, वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता डॉ. दीपक कुमार, विकास ताखर, लोकेश प्रजापत, विजेन्द्र वर्मा एवं रामप्रसाद मौजूद रहे।

प्रजापति समाज के सात जोड़े परिणय सूत्र में बंधे



सम्मेलन में नवविवाहित जोड़ों का पाणीग्रहण संस्कार सम्पन्न कराया।

विवाह सम्मेलन महत्वपूर्ण कड़ी है। ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देना चाहिए। फिजुल् खर्ची के साथ-साथ समाज के कमजोर लोगों को संबल मिलता है। इस

दौरान समिति अध्यक्ष संतुलाल, कालूराम माचीवाल, सुरेशचंद, सुवालाल, मातादीन, कालूराम दुहारिया, शंकरलाल, बनवारी, सुंदर

कुमार, रमेश, हंसराज, राकेश, रोहिताश, भागीरथमल, रामचंद्र, मुकेश, पूर्व पार्षद पुष्पा देवी, सजना देवी, मोहन, देवी सहाय, आदित्य,

- श्रीयादे माता प्रजापति विकास समिति त्रिवेणीधाम का सामूहिक विवाह सम्मेलन सम्पन्न**

किशनलाल, आदि ने अतिथियों व भामाशाहों का सम्मान किया। अतिथियों ने वर वधु को सुखी दाम्पत्य का आशीर्वाद प्रदान किया। समारोह में प्रजापति समाज समिति अहमदाबाद, बड़ोदा, भावनगर, मेहसाणा, अलवर समिति पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में समाजबेधुओं ने भाग लिया।

समिति एवं भामाशाहों द्वारा वर वधु को विवाह सम्मेलन में बैड, अलमारी, सिलार्ड मशीन, एलईडी टीवी, मिक्सी, कुलर, पंखा, बर्तन, आभूषण, घड़ी सहित विभिन्न प्रकार का सामान उपहार स्वरूप भेंट किया। महिलाओं ने वधुओं को एक-एक साड़ी कन्यादान स्वरूप भेंट की।

नकबजनी की वारदात का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी अपने हैंड बैग में हमेशा ताला तोड़ने के लिए फोल्डिंग सरिया रखकर चलता था

- भीलवाड़ा, (निसं)।** शहर की कोतवाली थांना पुलिस ने बाजार नम्बर दो स्थित दुकान में हुई नकबजनी की वारदात का राजकांप एप की मदद से खुलासा किया है। पुलिस ने घटना में शामिल शातिर नकबजन पवन मीणा निवासी बड़ा ऊँचा, थांना छबड़ा (जिला बारां) को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजस्थान के विभिन्न जिला मुख्यालयों पर रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में नकबजनी और लूट की 27 वारदातों में चालानशुदा रह चुका है। आरोपी अपने हैंड बैग में हमेशा ताला तोड़ने के लिए फोल्डिंग सरिया रखकर चलता था।

जानकारी के अनुसार 18 नवंबर को परमानंद गुरनानी निवासी कुमुद विहार ने रिपोर्ट दी कि उनकी दुकान-होरा ट्रेडर्स, बाजार नंबर दो का शटर टूटा हुआ मिला है। दुकान के सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सुबह 5:15 बजे एक बदमाश गले का ताला तोड़कर 2,45,००0 रुपये चोरी कर ले गया। इस रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू की गई। कोतवाली पुलिस की विशेष टीम ने पड़ताल व सीसीटीवी फुटेज का बारीकी से विश्लेषण किया।

एक फुटेज में स्पष्ट चेहरा दिखने पर उसे राजकांप ऐप में फोटो मैच किया गया, जिसमें आरोपी की पहचान पवन मीणा के रूप में हो गई। पोर्टल पर सर्च करने पर पता चला कि आरोपी राजस्थान के लगभग सभी जिला मुख्यालयों के रेलवे स्टेशन क्षेत्रों में नकबजनी और अकेली महिलाओं से लूट करने के मामलों में 27 बार चालानशुदा है। आरोपी के गांव में तलाश की गई, जहां यह सामने आया कि वह वर्षों से वहां नहीं गया। उसके तरीके को देखते हुए भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और अजमेर रेलवे स्टेशनों पर निगरानी शुरू की गई।

निगरानी के दौरान आरोपी की पहचान कांस्टेबल संजय जीनगर और कांस्टेबल भूपेंद्र गिरी ने की। रौकी के दौरान पवन मीणा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी

सरकारी स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की नहीं मिली राशि

कहीं संस्था प्रधान की जेब, कहीं शाला विकास कोष से जमा हो रहे स्कूलों में बिजली-पानी बिल

बीकानेर, (निसं)। सरकारी स्कूलों में सामान्य शैक्षिक सह शैक्षिक गतिविधियों सहित शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट का प्रावधान है। नियमों के मुताबिक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से सरकारी स्कूलों को मिलने वाले इस बजट की 7० प्रतिशत राशि दिसंबर माह तक खर्च करने का प्रावधान है। वर्तमान शिक्षा सत्र में हालात यह हैं कि आधा सत्र भी जाने के बाद भी जिले के 725 उच्च माध्यमिक स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट का एक रुपया भी नहीं मिला है। हालात यह हैं कि संस्था प्रधानों को अपनी जेब से या फिर शाला विकास

कोष से बिजली-पानी के बिल सहित न्यूज पेपर और स्टेशनरी भुगतान करना पड़ रहा है, जिससे सरकारी स्कूलों में होने वाले व्यय को लेकर संस्था प्रधान परेशान हैं। सरकारी स्कूलों में जमा राशि से अबकी बार दीपावली के पर्व पर सरकारी स्कूलों का रंग रोगन एवं छोटा-मोटा मरम्मत का कार्य करवाने में खर्च हो गई। जिसके कारण सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए कई कार्य अधर में लटके हुए हैं या संस्था प्रधान एवं शिक्षक अभी अपने जेब से राशि खर्च कर रहे हैं।

नामांकन के आधार पर सरकारी स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट की राशि निर्धारित है। इस राशि से स्कूल की

स्वच्छता, बच्चों के लिए पानी, चौक, डस्टर आदि की व्यवस्था की जाती है। अब तक केवल महात्मा गांधी स्कूल सहित प्राथमिक के 5० प्रतिशत स्कूलों में ही राशि उपलब्ध कराई गई है, जबकि राशि से अबकी बार दीपावली के पर्व पर सरकारी स्कूलों का रंग रोगन एवं छोटा-मोटा मरम्मत का कार्य करवाने में खर्च हो गई। जिसके कारण सरकारी स्कूलों के संचालन के लिए कई कार्य अधर में लटके हुए हैं या संस्था प्रधान एवं शिक्षक अभी अपने जेब से राशि खर्च कर रहे हैं।

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से बीकानेर जिले में संचालित प्रारंभिक शिक्षा के 1485 स्कूलों को 5० प्रतिशत राशि के तहत दो किस्तों में लगभग 1.57 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। जबकि 725 उच्च माध्यमिक स्कूलों को 6 महीने बाद भी बजट की प्रथम किस्त का भी भुगतान नहीं हुआ है।

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन व उड़द की खरीद शुरु

बूंदी, (निसं)। राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर सोयाबीन एवं उड़द खरीद के लिए बूंदी, हिण्डोली, के. पाटन (कापरने, सुमेरगंजमण्डी), नैगवों (देई) में क्रय विक्रय सहकारी समितियों में एवं खटकड़, भैरूपुरा औझा, अरनेटा, बसोली, गोठड़ा, पेंच की बावड़ी, जरखोदा व करवर में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कुल 13 क्रय केन्द्र जिले

में स्थापित किये गये हैं। सहकारी समिति के उप रजिस्ट्रार मुकेश मोहन गर्ग ने बताया कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रू. एवं उड़द का समर्थन मूल्य 78०० रू. प्रति क्विंटल निर्धारित है। 24 नवम्बर से खरीद शुरु हो चुकी है, खरीद प्रक्रिया के सुचारु रूप से संचालन के लिए राजफैड जयपुर द्वारा पंजीकृत किसानों को अथनी जिस निर्धारित दिनांक

आजेएस भर्ती में उम्र में छूट को लेकर दाखिल याचिका खारिज

- न्यायिक सेवा भर्ती में उम्र की छूट मांगकर भूल गया याचिकाकर्ता, जस्टिस बदलते रहे, कोर्ट ने केस खारिज किया**

पंचायत समिति, जिला परिषद और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 4० वर्ष तक (5 साल की छूट) का लाभ दिया जाता है। वकील ने सवाल उठाया कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारी भी उसी तरह का प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। फिर उनके साथ भेदभाव क्यों? वकील ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उकलंघन बताया था और मांग की थी कि केंद्रीय कर्मचारियों को भी राज्य कर्मचारियों के समान छूट मिलनी चाहिए।

उस समय हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जवाब दिया गया था कि नियम बनाने का अधिकार नियोजता का है। उन्होंने तर्क दिया था कि आयु में छूट एक रियायत है, इसे अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। प्रशासन का कहना था कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को लाभ देने के लिए स्वतंत्र है और यह जरूरी नहीं कि वही लाभ

केंद्र के कर्मचारियों को भी दिया जाए। इस केस का सबसे दिलचस्प पहलू 25 अगस्त 2०15 का वह आदेश है, जिसने हजारों अप्रार्थियों की उम्मीदें जगा दी थीं। तत्कालीन जस्टिस गोविंद माधुर और जस्टिस जयश्री ठाकुर की डिवीजन बेंच ने ललित कुमार को अंतरिम आदेश के तहत परीक्षा में बैठने की अनुमति दी थी। जब रिजल्ट सील बंद लिफाफे में कोर्ट के सामने खोला गया तो पता चला कि ललित कुमार प्रौलिम्स (प्रारंभिक परीक्षा) की कट-ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे। कोर्ट की इतनी गंभीरता के बावजूद याचिकाकर्ता ने केस की पैरवी करना छोड़ दिया। इस केस के ऑनलाइन कोर्ट रिकॉर्ड गवाह हैं कि कैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा खुद याचिकाकर्ता की अनदेखी से समय की भेंट चढ़ गया। याचिकाकर्ता के वकील की उपस्थिति आखिरी बार 27 नवंबर 2०18 के आदेश में दर्ज है।



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर एवं उदयपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ उपस्थित थे।

सभी कार्यकर्ता निकाय व पंचायतीराज चुनावों की तैयारी करें- भजनलाल

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर व भरतपुर संभाग के पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की

जयपुर, 26 नवम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर भरतपुर एवं उदयपुर संभाग के भाजपा जिला अध्यक्षों एवं मंडल अध्यक्षों तथा कार्यकर्ताओं के साथ संगठन से संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा में मेहनती और निष्ठावान कार्यकर्ता संगठन से लेकर समाज व देश की सेवा में तत्पर रहता है, जिससे वह सदैव आगे बढ़ता है तथा सम्मान भी प्राप्त करता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार को तरह है तथा प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए पार्टी का कार्य सर्वोपरि है, इसलिए दिए गए दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाएं तथा मंडल स्तर की नियमित बैठकें भी करें। उन्होंने कहा कि मेहनती कार्यकर्ता और पदाधिकारी राज्य

- मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि सभी जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष जनसेवा के साथ समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए काम करें।
- बैठक में मुख्यमंत्री के साथ भरत राठौड़, प्रेम चन्द बैरवा, अरुण चतुर्वेदी, घनश्याम तिवाड़ी, अशोक परनामी व राजेन्द्र राठौड़ भी शामिल हुए।

साथ समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कार्य करें। संगठन में युवाओं को केन्द्र व राज्य के कार्यक्रमों से जोड़ें और उन्हें जिम्मेदारी भी दें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भेद-भाव और तुष्टीकरण के आधार पर बाड़ों और पंचायतों को जोड़ा और तोड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने तथ्यों और आवश्यकता को देखते हुए पुनर्गठन के कार्य को पूरा किया है, इसलिए सभी कार्यकर्ता आने वाले निकाय और पंचायतीराज चुनाव की तैयारी करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक से अधिक संख्या में नए लोगों को पार्टी से जोड़ें तथा उन्हें जिम्मेदारी दें। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता को काम के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी मिलता है।

सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और 2 वर्षों की उपलब्धियों को सोशल मीडिया एवं अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से आमजन तक पहुंचाएं। वे पार्टी की रीति और नीति को भी हर वर्ग तक पहुंचाने का कार्य करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष जनसेवा के साथ-

राबड़ी देवी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तेजस्वी से उस बँगले को खाली करने के लिए कह दिया गया। तेजस्वी ने इस निर्णय/आदेश को अदालत में चुनौती दी, मगर 19 फरवरी 2019 के पटना हाई कोर्ट के फैसले में उनके खिलाफ निर्णय आया और राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वे सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों से बँगला, गाड़ी, सुरक्षा और स्टाफ की सुविधाएँ वापस ले ली जायें। इस फैसले का असर राबड़ी देवी, जीवन राम मांझी और जगन्नाथ मिश्र पर भी पड़ा, लेकिन राबड़ी देवी के पास 10, सर्कुलर रोड वाला बँगला इसलिए बना रहा, क्योंकि वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष थीं। आज भी वे उसी पद पर हैं, लेकिन नई सरकार का अब इस बँगले को लेकर अलग रुख है। यह बँगला प्रकरण इस बात का संकेत है कि नई नीतीश सरकार लालू परिवार से जुड़े लंबित केसों में नरमी नहीं बरतेगी।

विद्याधर नगर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया, खो-नागौरियन सहित, जयपुर के लगभग हर हिस्से में पिछले कुछ महीनों से लैपर्ड की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। आबादी क्षेत्र और हाई-सिक्चरिटी ज़ोन में लैपर्ड का मुवमेंट वन विभाग और पुलिस दोनों के लिए चुनौती बन गया है।

ट्रंप की लाज बचाने के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

है। प्रस्तावित समझौते की पूरी शर्तें अभी सामने नहीं आई हैं और सबसे अहम बात, रूस ने सार्वजनिक रूप से अभी तक किसी फ्रेमवर्क को मंजूरी नहीं दी है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के सतर्क बयान, जिसमें उन्होंने अमेरिकी पहल को स्वीकार तो किया लेकिन रूस की स्थिति स्पष्ट नहीं की, यह बात हालात की नज़ाकत को स्पष्ट दे रहा है। अगर रूस ने खुलकर सहमति नहीं दी, तो ट्रम्प पर अचूरी कूटनीति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लग सकता है। ऐसी स्थिति उनके लिए उल्टी भी पड़ सकती है और आलोचनाएं और तेज हो सकती हैं।

फिर भी, ट्रम्प प्रशासन को विश्वास है कि बातचीत में बनी गति घरेलू राजनीति की धार बदल सकती है। खबर है कि अमेरिकी सेना के सचिव डैन ड्रिस्कॉल रूस के अधिकारियों से अब् धाबी में बातचीत कर रहे हैं, ताकि मॉस्को की सहमति सुनिश्चित की जा सके। वाइट हाउस भी संकेत दे रहा है कि ऐतिहासिक समझौता होने वाला है। अगर ट्रम्प खुद को इस शांति प्रयास का सूत्रधार साबित कर पाए, या कम से कम वह ऐसे राष्ट्रपति साबित हूये, जिन्होंने सभी पक्षों को फिर से बातचीत की मेज

पर बैठाया, तो इससे विरोधियों की आलोचना कम हो सकती है और हाल के हफ्तों में कमजोर हुई उनकी राजनीतिक स्थिति फिर मजबूत हो सकती है।

डेमोक्रेट अभी भी सावधान और संदेहपूर्ण है। उनका कहना है कि इस प्रशासन के कई विदेश नीति प्रयासों ने बड़े-बड़े दावे तो किए, लेकिन स्थायी परिणाम नहीं दिए। यूरोपीय सहयोगियों को भी चिंता है कि अमेरिका तेज़ प्रगति के चक्कर में दीर्घकालीन क्षेत्रीय स्थिरता की उपेक्षा कर रहा है। हालांकि आलोचकों भी मानते हैं कि यदि शांति समझौता वास्तव में सफल होता है, तो इसका राजनीतिक प्रभाव बेहद बड़ा होगा।

फिलहाल, अभी तो ट्रम्प की प्रैसिडेंसी की कमजोरियाँ साफ दिखाई दे रही हैं, गिरते सर्वेक्षण, कांग्रेस के बेचैनी और जनता की बढ़ती नाखुशी। लेकिन यूक्रेन शांति पहल ने महीनों बाद उन्हें पहला मजबूत मौका दिया है, जिससे उन्हें अपनी नेतृत्व छवि को दोबारा गढ़ने का एक मौका मिल सकता है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है और रूस भी इसमें शामिल होता है, तो राष्ट्रपति ट्रम्प फिर से राजनीतिक गति पा सकते हैं। लेकिन अगर बातचीत अटक

गई, तो उनकी कूटनीतिक महत्वाकांक्षा और वास्तविकता के बीच का अंतर उनकी राजनीतिक मुश्किलों को और बढ़ा सकता है।

आने वाले कुछ सप्ताह, पूर्वी यूरोप में भी और अमेरिकी राजनीति में भी, तय करेंगे कि ट्रम्प की यह शांति पहल एक ऐतिहासिक उपलब्धि बनती है या एक और ऐसी खबर, जो उनके डगमगाते कार्यक्रम में थोड़ी देर चर्चा के बाद गायब हो जाती है।

दिल्ली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कार बम धमाके करने वाले उमर के छह और खास साधियों को गिरफ्तार किया है।

एजेंसी इस आत्मघाती धमाके की सिलसिले में अलग-अलग सुरागों की जांच कर रही है। इस भयानक हमले में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए संबंधित पुलिस के साथ मिलकर कई राज्यों में एनआईए अधिकारी तलाशी अभियान चला रहे हैं। इस आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने की एनआईए कोशिशें जारी हैं।

बिहार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

यदि यह गतिरोध जारी रहता है, तो स्पीकर का चुनाव, जो सामान्यतः एक रूटीन प्रक्रिया होती है, नई सरकार के लिए पहला बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। फिलहाल, सभी की नज़रें इस पर टिकी हैं कि क्या दोनों गठबंधन पार्टियां 1 दिसम्बर को विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले इस बहती जा रही दरार को पाटने में सफल हो पाएंगी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली, 26 नवंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन (एससीबीए) की ओर से आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभालने के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय कानूनी मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। मुख्य न्यायाधीश ने संविधान दिवस को एक उत्साहवर्धक अवसर बताया और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में बार की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने अधिवक्ताओं को संवैधानिक आदर्शों के मशाल-वाहक बताते हुए कहा कि बार की गहरी विद्वता संवैधानिक व्याख्या की नींव बनाती है। न्यायमूर्ति सूर्य कांत ने कानूनी दिग्गजों जैसे नानी पालकीवाला, एम.सी. सीतलवाड़, संविधान निर्माताओं डॉ. बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर के योगदान को याद किया और कहा कि भारत की कानूनी यात्रा उन अधिवक्ताओं द्वारा आकार दी गई है जिनकी बुद्धि और ईमानदारी ने राष्ट्र के विकास का मार्गदर्शन किया।

सीबीआई ने आईटीएटी सदस्य, एडवोकेट व अपीलकर्ता को रिश्तत लेते गिरफ्तार किया

सीबीआई के छापों में एक करोड़ रुपए से अधिक की राशि बरामद हुई है

- आयकर अपील ट्रिब्यूनल की न्यायिक सदस्य डॉ. सीता लक्ष्मी की सरकारी कार से 30 लाख रुपये की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। सीबीआई ने जाँच का दायरा बढ़ाकर जयपुर, कोटा व अन्य शहरों में आरोपियों के ठिकानों पर छापे मारे।

ही आईटीएटी के एक एडवोकेट राजेंद्र सिसोदिया को 5.50 लाख रुपये की रिश्तत राशि के साथ गिरफ्तार किया गया। यह रिश्तत कथित तौर पर अपीलकर्ता ने हवाला नेटवर्क के माध्यम से दी थी। इसी कड़ी में ऑपरेशन के अगले ही दिन बुधवार को आईटीएटी जयपुर की न्यायिक सदस्य डॉ. एस. सीता लक्ष्मी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी सरकारी कार से 30 लाख रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। रिश्तत देने वाले अपीलकर्ता मुजम्मल को भी बुधवार को ही गिरफ्तार कर लिया गया है।

सीबीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए जयपुर, कोटा व अन्य शहरों

में आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी की। जिसमें एक करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की गई। इसके साथ ही संदिग्ध ट्रांज़ेक्शन, संपत्ति के दस्तावेज और अन्य संदिग्ध दस्तावेज भी सीबीआई के हाथ लगे हैं। जो इस खेल में संगठित सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहे हैं। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर सीबीआई ने तीन दिन के रिमांड पर लिया है। जांच एजेंसी ने दावा किया है कि इस गिरोह में उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी शामिल थे। जो न्यायिक प्रक्रिया को पैसे के दम पर रौंदने का प्रयास कर रहे थे। इस मामले में सीबीआई की जांच और अग्रिम अनुसंधान जारी है।

दिल्ली विस्फोट : जांच एजेन्सियों ने डॉ. आदिल की डिलीट चैट वापस हासिल की

फोन संदेशों में आदिल बार-बार पैसों की मांग कर रहा है

- सूत्रों के अनुसार 5,6,7, और 9 दिसम्बर 2025 के संदेशों में तत्काल पैसों की आवश्यकता बताई गई। अनुमान है कि यही पैसा हमले में खर्च हुआ।

करता दिखाई देता है। यहां तक कि उसने एक बार तो अपनी तनख्वाह तक एडवांस में मांगी।

संदेशों के जरिए हुई बातचीत 5, 6, 7 और 9 सितम्बर 2025 की है। इनमें उसने तत्काल पैसों की आवश्यकता बताई है। जांच एजेंसियों का अनुमान है कि यही पैसा हमले में खर्च हुआ।

सूत्रों के अनुसार, कुल 26 लाख रुपये में से 8 लाख रुपये आदिल ने उपलब्ध कराए थे। पूछताछ में गिरफ्तार आरोपी मुजम्मिल ने बताया कि समूह में आदिल को खर्चांची कहा जाता था। जांच में यह भी पुष्टि हुई है कि डॉ. आदिल कथित घटनाओं से ठीक पहले श्रीनगर से 11 अक्टूबर को दिल्ली आया था।

नयी दिल्ली, 26 नवम्बर। दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले में जांच एजेंसियों ने बुधवार को दावा किया कि उन्हें डॉ. आदिल के डिलीट किए गए व्हाट्सअप चैट को दोबारा हासिल करने में सफलता मिल गयी है।

इस मामले में डा. आदिल एक मुख्य आरोपी है, जिसकी गिरफ्तारी से फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल का पता चला है।

जांच एजेंसियों को दोबारा मिले इन संदेशों में उसकी आर्थिक तंगी की स्थिति स्पष्ट दिखती है। वह बार-बार पैसों की मांग करता दिखाई देता है। जांचकर्ताओं का संदेह है कि यही रकम उस हमले में इस्तेमाल हुई, जिसमें आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी ने अपनी आई20 कार में विस्फोट कर

‘बाहरी बाधाओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहेगी’

आईएमएफ ने भारतीय आर्थिक वृद्धि की तारीफ की और अनुशासन बनाये रखने की सलाह दी

- आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाये गये 50 प्रतिशत आयात शुल्क का प्रभाव घरेलू उपभोग बढ़ने के कारण कम होगा।

लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में वास्तविक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर 6.5 प्रतिशत और 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में 7.8 प्रतिशत रही है। उसने कहा कि खाने-

पीने की चीजों की महंगाई कम होने से मुद्रास्फीति की दर में भारी गिरावट आयी है। वित्तीय और कॉर्पोरेट सेक्टर मजबूत बने हुए हैं, वित्तीय अनुशासन बेहतर हुआ है और चालू खाते का घाटा कम हुआ है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी

बाधाओं के बावजूद, अनुकूल घरेलू कारकों की वजह से वृद्धि दर मजबूत बनी रहेगी और अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क का प्रभाव घरेलू उपभोग बढ़ ने की वजह से कम होगा। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हालांकि कटौती और आयकर छूट की सीमा बढ़ ने के मद्देनजर आईएमएफ ने वित्तीय अनुशासन बनाये रखने की जरूरत पर बल दिया है।

कार्यकारी निदेशकों ने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर जीएसटी और व्यक्तिगत आयकर में कटौती के प्रभाव पर नज़दीकी नज़र रखने की सलाह दी है।

‘अनियंत्रित ऑन लाइन गेमिंग ऐप आतंकवाद को फंड करते हैं’

केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में दाखिल हलफनामे में यह खुलासा किया

- हलफनामे में भी यह भी कहा गया है कि विज्ञापनों, सैलिब्रिटी और सोशल इन्फ्लुएंसर के प्रचार से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म युवाओं और कमजोर तबकों में तेजी से फैल रहा है।

नई दिल्ली, 26 नवम्बर। केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिना नियम वाले ऑनलाइन गेमिंग ऐप का संबंध आतंकवाद को वित्तीय मदद देने और धन शोधन से जुड़ा है। इसलिए इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को नियंत्रित करने के लिए कानून लाना जरूरी था। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि वे इस मामले की कल यात्री गुहार को सुनवाई करने का प्रयास करेंगे।

सरकार की ओर से दाखिल हलफनामे में कहा गया है कि बिना रोक-टोक के बढ़ रहे ऑनलाइन गेमिंग वाले गेम्स का संबंध वित्तीय धोखाधड़ी, धनशोधन, धूर्त (टैक्स) चोरी और कई मामलों में आतंकवाद के लिए पैसों जुटाने से भी जुड़ा है। यह स्थिति राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य

की अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। हलफनामे में यह भी कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बड़े पैमाने पर विज्ञापनों, सैलिब्रिटी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के प्रचार से युवाओं और कमजोर तबकों तक तेजी से पहुंच रहे हैं, जिससे उनका प्रभाव बढ़ रहा है। सरकार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग वाले गेम्स का व्यक्तियों, परिवारों, समाज और पूरे देश पर बुरा असर पड़ रहा है। इसे कूटनीतिक माध्यम, प्लोअरिडम और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जैसे तकनीकी पहलुओं के चलते, ये

कंपनियां विदेशों से संचालित होती हैं, घरेलू और राज्य स्तर के कानूनों को नज़रअंदाज करती हैं और इन्हें रोकना बेहद मुश्किल है। इसी वजह से 2025 का ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन कानून बनाया गया।

सरकार ने कहा कि जनता की भलाई के लिए यह जरूरी था कि केन्द्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी ले और एक सुरक्षित, व्यवस्थित और नवाचार को बढ़ावा देने वाला डिजिटल माहौल तैयार करे।

‘कर्नाटक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

वाले हैं। यह सत्ता-संघर्ष कर्नाटक इकाई में गुटबाजी की गहरी जड़ों को उजागर करता है, जहां एक समूह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का समर्थन कर रहा है और दूसरा डीकेएस को सत्ता सौंपने की मांग करता है।

आज दोहरा कर यह स्वीकारोक्ति पिछले हफ्ते की उस टिप्पणी से एक यू-टर्न भी है, जिसमें पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने, जून की तरह ही, यह कहा था कि कर्नाटक में सब कुछ ठीक है।

